सीकर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, हिंडौन, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर से प्रसारित

विज्ञापन के लिऐ : 9314505000 लॉग ऑन करें: www.chamaktarajasthan.com

RNI No. RAJHIN/2011/40950

राज्य तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त

चमकता राजस्थान

Email- chamaktarajasthan8789@gmail.com जयपुर से प्रकाशित एवं प्रसारित डाक पंजीयन संख्या: RJ/JPC/D19/2022-23

जयपुर, बुधवार, 14 जून 2023 वर्ष : 13 अंक : 290 पृष्ठ : 8 दैनिक प्रात: कालीन मूल्य : 1 रूपया

जे डी ए जोन 5 के आधिकारियों ने सरकारी धन का दुरूपयोग कर किया बड़ा घोटाला ?

टूटी सीवर लाइन पर डालते रहे डामर की परत पर परत

अत्रि कुमार दाधीच

चमकता राजस्थान, जयपुर। आपने मखमल के कपड़े पर टाट का पैबंद की कहावत तो बहुत सुनी होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है, वह टूटी सीवर लाइन पर मखमल (डामर) का पैबंद लगा रहा है!जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन नंबर 5 में स्थित श्याम नगर में अभी कुछ दिनों पूर्व ही अयोध्या पथ पर सीवर लाइन के कारण गहरा खड्डा होने की जानकारी सामने आई थी हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में गहरी छानबीन की तो पता लगा कि कुछ समय पूर्व भी यहां पर 20 फुट का गहरा खड्डा हुआ था जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम ने लीपापोती कर मलवा डालकर उस पर डामर की परत चढ़ा दी शुक्र है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई ! इसी अयोध्या पथ पर पहले भी टूटी सीवर लाइन के कारण गहरा खड्डा हो चुका है!नगर निगम तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की भ्रष्टाचार की बानगी तो देखिए कुछ समय पूर्व इसी जगह पर टूटी सीवर लाइन के कारण गहरा खड्डा हुआ था तब भी अधिकारियों की नींद नहीं खुली और मलवा डालकर उस सड़क पर डामर की परत चढ़ा दी गई, यही हाल अब राम पथ पर होने जा रहा है आनन-फानन में अयोध्या पद पर तो नई सीवर लाइन डाली जा रही है लेकिन राम पथ पर जो डामर की परत चढ़ा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है उसका जिम्मेदार कौन?

राम पथ पर भी सीवर लाइन टूटी,हुआ गहरा खड्डा

भाजपा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाडी के मकान के सामने राम पथ पर वही हादसा होते-होते बचा जब सीवर लाइन के कारण वहां पर खड्डा हो गया! गौरतलब है कि अभी वहां पर सड़क पर डामर की परत चढ़ाने का कार्य तेजी से चल रहा है वहां पर कॉलोनी वासियों से पता चला कि डामर की परत के कारण कई मकान मेन रोड से नीचे आ गए हैं तथा फुटपाथ खत्म हो गया है! इसी के साथ विकास नहीं होने के कारण तथा मेन रोड का ढलान संपर्क सड़कों पर होने के कारण बारिश का पानी संपर्क सड़कों पर भरा रहता है, जिससे मच्छरों तथा गंदगी से कॉलोनी वासियों का बुरा हाल रहता है!

राम पथ पर टूटी सीवर लाइन के कारण हुआ खड्डा, पास में लीपापोती के लिए डाला गया मलवा

अयोध्या पथ पर टूटी सीवर लाइन के कारण हुआ खड्डा

टूटी सीवर लाइनों पर डाल रहे नई डामर की परत,आस पास की कालोनियां सड़क को तरसी

श्याम नगर के पास स्थित अन्य कॉलोनीयों जैसे कटेवा नगर,देवी नगर में कई जगह सीवर लाइन डाली गई थीं उन पर अभी तक रोड नहीं बनाई जा सकी है जबकि श्यामनगर मैं पुरानी टूटी सीवर लाइनों पर ही डामर की परत चढ़ाई जा रही है !

राम पथ पर डाली गई नई डामर की परत

जिम्मेदारों ने नहीं उठाया फोन

घटना के बाद हेरिटेज नगर निगम के एक्सईएन दिनेश गुप्ता ने फोन नहीं उठाया, यही स्थिति जेडीए एक्स ई एन विनोद कृष्णिया की भी रही!

किसी दबाव में डाली जा रही है या कमाई का जरिया बन चुकी है

हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में गहरी छानबीन की तो पता लगा कि आसपास की कॉलोनियों वाले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास जाकर रोड निर्माण तथा सीवर लाइनों के लिए ठोकरे खा रहे हैं वही श्याम नगर में बिना किसी कारण के डामर की परत चढ़ाई जा रही है!

अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दे पहुंचाया लाभ

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है अधिकारियों ने सीवर लाइन को दुरुस्त कराए बिना मलवा डालकर इतिश्री कर ली और लाखों का बिल अपने चहेते ठेकेदारों को उठवा दिया! अब मामले नगर निगम तथा जेडीए एक दूसरे पर डाल उनके अधिकारी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं!

भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण + नरक निगम =भ्रष्टाचारी अधिकारीयों का स्वर्ग

जयपुर विकास प्राधिकरण को भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नरक निगम बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि दोनों के अधिकारीयों के लिए विभाग भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बनता जा रहा हैं, जो अधिकारी एक बार इन विभागों में पदस्थ हो जाता है वह दोबारा दूसरे विभाग में जाने की कल्पना से भी कांप उठता है क्योंकि दोनों विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं,अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ जगजाहिर है, जयपुर शहर में दोनों विभागों का कार्य अलग-अलग बटा हुआ है लेकिन फिर भी दोनों विभागों के अधिकारियों का चोली दामन का साथ हर जगह नजर आता है क्योंकि क्षेत्र के कई कार्य जहां जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आते हैं वहीं उसी क्षेत्र में नगर निगम के अधीन भी कई कार्य आते हैं, ऐसे में विभागों के अधिकारी एक दूसरे पर मामले को डाल पल्ला झाड़ लेते हैं और ठेकेदारों से सांठगांठ कर सरकारी रुपयों का दुरुपयोग करते हैं!

नीतीश कैबिनेट से जीतनराम मांझी के बेटे का इस्तीफा

बिहार सीएम की विपक्षी एकता बैठक से 10 दिन पहले पद छोड़ा

पटना (एजेंसी)। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए 18 दलों की बैठक बुलाई है। बैठक से 10 दिन पहले मंगलवार को बिहार की महागठबंधन सरकार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। HAM के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे डॉ. संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को इस्तीफा भेज दिया है। सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं। बिहार में पार्टी के 4 विधायक हैं। इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा- नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। वे हमारी पार्टी ॥रूका विलय अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में करवाना चाहते हैं। पार्टी बचाने के लिए हमने इस्तीफे का विकल्प चुना है। अभी हम सरकार से अलग हुए हैं, महागठबंधन से नहीं। महागठबंधन में रखना है या नहीं यह लालू और नीतीश तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मांझी के NDA में जाने की चर्चा है।

उत्तर भारत में भूकंप, दिल्ली-एनसीआर समेत 5 राज्यों में महसूस किए गए झटके

पटना (एजेंसी)। देश के उत्तरी हिस्से में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को ही तिब्बत के शिजांग में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, सुबह 3-23 बजे यह भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 106 किलोमीटर नीचे था। पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लोनावला के पास एक ऑइल टैंकर पलट गया, जिससे भीषण आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हैं। अचानक टैंकर ने नियंत्रण खो दिया और पलट गया, जिसके बाद सड़क पर ऑइल गिरने से भीषण आग लग गई।

कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का सचिवालय महाघेराव, कार्यकर्ताओं का उमडा जनसैलाब:-सीपी जोशी

चमकता राजस्थान, जयपुर। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस आमने-सामने हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ जयपुर में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। चंद्र प्रकाश (सीपी) जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पर जमावड़े के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता-नेता सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्किल पर रोक लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कर आगे बढ़ने की कोशिश की पर पुलिस की संख्याबल के आगे उनकी नहीं चली। वे वहीं कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बड़े नेताओं की मौजूदगी में वहीं धरना-प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा नेता-कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला करते हुए कहा कि यह सरकार जाएगी नहीं, डिलीट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कहा, एक समय था, जब कहा जाता था चेचक का रोगी बताओ 10 हज़ार पाओ। अब वो समय आएगा जब कहा जाएगा कि कांग्रेस का विधायक बताओ, 1 लाख रुपए पाओ। वहीं, बीजेपी मुख्यालय पर विधायक अशोक लाहोटी ने कहा- पहले सरकार ने महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा की थी। अब कह रही है, हम खाते में पैसे देंगे। महिलाएं खुद मोबाइल खरीद लें। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि पहले पैसे अकाउंट में आ जाए, तभी मोबाइल खरीदना। इस सरकार के पास पैसे ही नहीं है। कहीं आप मोबाइल भी खरीद लो और पैसे भी नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। भाजपा का दावा है कि आज के प्रदर्शन में जयपुर सहित दूसरे जिलों से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं।

ज्ञानदेव आहूजा के बिगड़े बोल: बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा- राहुल गांधी और अशोक गहलोत जूते खाने का काम करते हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान ने 1947 में लाखों लोगों को मरवाया।

1984 में हजारों सिखों को मरवाया। वहीं, 1990 में करीब 2 हजार कश्मीरियों को मरवाने का काम किया हैं। प्रभारी अरुण सिंह ने कहा- इस बार तो गहलोत सरकार जाएगी ही। वहीं अगले 10 से 15 साल तक सरकार फिर

रेरा जज पर बिल्डर ने लगाए पक्षपात करने के आरोप

ऑर्डर के पालना के बजाए जजमेंट देने वाले के खिलाफ की शिकायत

चमकता राजस्थान, जयपुर। राजस्थान रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा राजस्थान) में जजमेंट देने वाले सदस्य पर बिल्डर ने पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उसी के खिलाफ शिकायत दे दी। बिल्डर के इस कदम के बाद कोर्ट ने बिल्डर पर आदेशों की पालना नहीं करते हुए इसे अवहेलना माना और बिल्डर ग्रुप के सभी डायरेक्टर और उनके सीए को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए है। ऑथोरिटी के सदस्य सलविंदर सिंह सोहाता ने आदेशों की अवेहलना विक्की वर्मा की याचिका पर दिए निर्णय की पालना नहीं करने के मामले में माना है। वर्मा ने बिल्डर पर प्रोजेक्ट में समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देने की शिकायत करते हुए पूरा पैसा ब्याज सहित वापस देने की याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑथोरिटी के सदस्य बिल्डर ग्रुप को बिना ब्याज के पैसा लौटाने के आदेश 6 अप्रैल 2023 दिए थे। इस आदेश के बाद भी बिल्डर ग्रुप की ओर से परिवादी को रिफंड नहीं किया। इसके विपरित इसी आदेशों के खिलाफ बिल्डर ग्रुप ने एक शिकायत पत्र ऑथोरिटी में देते हुए सदस्य सोहाता पर पक्षपात पूर्ण निर्णय करने का आरोप लगाया। ग्रुप के सीए और रिप्रजेन्टेटिव ने आरोप लगाया कि हमने ऑथोरिटी से सुनवाई के लिए आगे की डेट मांगी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की और एक तरफ फैसला सुना दिया।

दो मामले में बिल्डर के पक्ष में सुनाया फैसला

पहले इसी प्रोजेक्ट में समय पर कब्जा नहीं देने के मामले दो अन्य याचिकाएं भी रेरा ऑथारिटी में लगी थी। ये याचिका जसमीत जैन, कुलविंदर सिंह की ओर से लगाई थी। उस याचिका दोनों ने बिल्डर पर समय पर कब्जा नहीं देने पर जमा पैसा रिफंड करवाने की मांग की थी। तब बिल्डर ने अपना पक्ष रखते हुए प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कही और कब्जा देने के लिए कहा।

उदयपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को निपटाएगी, भाजपा की चाल को जनता समझ चुकी

गहलोत बोले- हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे

चमकता राजस्थान, उदयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- राजस्थान में कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि अब धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करने वालों की चाल को जनता समझ चुकी है। गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को निपटाएगी। गहलोत मंगलवार को उदयपुर की लेकेंड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में बजरंग बली की जय बोलकर बटन दबाओ का नारा भी नहीं चला। अब लोग समझ गए है। गहलोत ने कहा- इस बार राजस्थान में हम लोग चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे, हमने क्या किया है। उसका मुकाबला विपक्ष करें। उन्होंने फिर कहा कि हमने वसुंधरा सरकार की कोई योजना बंद नहीं की, ये काम वे ही करते है, हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को वे बंद कर देते है।

विपक्ष के पास बहुत पैसा, हम कम संसाधन से लड़ेंगे

गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- ये लोगों को भड़काएंगे। इनके पास इतना पैसा हो गया की कोई सोच नहीं सकता। हमारे पास कम संसाधन है और हम उसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जनता होगी क्योंकि हमारी कथनी व करनी में अंतर नहीं है।

हम भाजपा को निपटा कर सरकार भी बनाएंगे

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाएगी के सवाल पर गहलोत ने कहा कि हम भाजपा को निपटा कर प्रदेश में फिर हमारी कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। वे बोले जहां जा रहा हूं वहां अच्छा माहौल दिख रहा है।

उदयपुर के धानमंडी में पब्लिक मीटिंग की इच्छा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर शहर के धानमंडी में उनकी पब्लिक मीटिंग करने की इच्छा है। वे बोले वहां किसी और पार्टी की सभा हुई होगी पर कांग्रेस की सालों से नहीं हुई है। यहां सभा होनी चाहिए।

संपादकीय

सूरज की लपटें

मौसम में इस बार वैसे ही कम अनिश्चितता नहीं है। मानसून ने देरी से केरल में दस्तक दी है और वह कुछ कमजोर भी दिख रहा है, इसलिए आशंकाएं ढेर सारी हैं। एक दूसरा सच यह भी है कि उत्तर और मध्य भारत में जब सूरज का ताप अपने चरम पर होना चाहिए, तब पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद दूसरा प्रगट हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें तो यह सब होना ही था। मगर इसी बीच वैज्ञानिक एक अन्य खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सूरज अपना रौद्र रूप दिखा सकता है और यह कई तरह से हमारे लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। बल्कि, उसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल की शुरुआत तक सूरज कई बार भभक सकता है और हमारी कई व्यवस्थाओं के लिए यह खतरा बन जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 5 जून को ऐसी ही एक भभक सूरज से निकली थी, जो सीधे हमारी पृथ्वी की दिशा में बढ़ी। हालांकि, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली यह लपट बहुत ताकतवर नहीं थी और धरती के पास पहुंचते-पहुंचते कुछ मंद भी पड़ गई। मगर हर बार शायद किस्मत इतनी अच्छी न हो। इंसानों के लिए सीधे सूरज को देखना संभव भी नहीं है और आंखों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सूरज की छवि देखें, तो उसकी सतह पर फफोले जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 11 साल बाद ये फफोले फूटते हैं और उनसे भारी मात्रा में ऊर्जा बेहद तेज गति से निकलती है। उसमें सिर्फ ताप नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगें भी होती हैं। इसे हम 'सोलर स्टॉर्म' यानी सूरज की आंधी या फिर 'सोलर फ्लेयर' या सूरज की लपट कहते हैं। यह हमेशा से ही होता रहा है और ज्यादतर मामलों में ये लपटें धरती के वातावरण पर एक हद से ज्यादा असर नहीं डाल सकतीं। लेकिन समस्या एक दूसरी जगह है। हम संचार तकनीक के जिस युग में हैं, वहां अनेक मानव निर्मित उपग्रह सुदूर आसमान में हर वक्त धरती के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। ये उपग्रह हमारे संचार नेटवर्क, हमारे टेलीफोन, हमारे टेलीविजन और इंटरनेट की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये चुंबकीय तरंगें और उनके साथ आने वाला ताप इन उपग्रहों और उसके साथ हमारी कई व्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देशों में तो इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति तक ठप हो सकती है। बहुत से बड़े उपग्रहों में यह व्यवस्था है कि उनके सोलर पैनल और एंटीना वगैरह को जरूरत पड़ने पर अंदर की तरफ समेटा जा सकता है और कुछ हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन सभी उपग्रहों में यह व्यवस्था नहीं है। हम सूरज को आदि मानते हैं। इस धरती पर जबसे इंसान है या यह जीव-जगत है, उससे पहले से सूरज अपनी जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि हाल-फिलहाल में उसकी फितरत में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। सूरज की लपटों के कारण जो समस्या हमारे सामने है, वह दरअसल सूरज से नहीं उपजी। वह इसलिए है कि आगे बढ़ने के प्रयासों में हमने उसकी इस फितरत को नजरअंदाज कर दिया और सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह संकट ही नहीं, आगे के लिए एक सबक भी है।

कठघरे में ट्रंप

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे जीवन में ढेर सारे विवाद खड़े किए हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने इतिहास ही बना दिया है। वह अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में बाकायदा आरोप तय किए गए हैं। इसके पहले वाटरगेट कांड पर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन उनके बाद राष्ट्रपति बने गेराल्ड फोर्ड ने इससे इनकार कर दिया। उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं लगी होगी, क्योंकि एक तो वह निक्सन की रिपब्लिकन पार्टी के ही थे। फिर यह खतरा भी नहीं था कि अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें निक्सन से कोई चुनौती मिले। लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ ऐसा नहीं है और अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ताल ठोकनी शुरू कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से फिलहाल वही सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। फिलहाल ट्रंप के खिलाफ मामला सिर्फ इतना है कि फ्लोरिडा में उनके मारा-लॉगों एस्टेट पर पिछले अगस्त में छापा मारकर सरकारी एजेंसी ने 11 हजार दस्तावेज जब्त किए थे, जिनमें कई बेहद गोपनीय दस्तावेज थे। बताते हैं, 33 बक्सों में बंद इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे भी थे, जो ईरान पर अमेरिकी हमले की योजना से संबंधित थे। ये दस्तावेज ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में हासिल किए थे, जिन्हें उन्होंने लौटाया नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय पहले अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी ने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन के पुराने निवास से भी कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए थे, जो उन्होंने तब हासिल किए थे, जब वह उप-राष्ट्रपति थे। एजेंसी के हिसाब से फर्क यह है कि ट्रंप ने उन दस्तावेजों को जानते-बूझते हुए भी न सिर्फ अपने पास रखा था, बल्कि लौटाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि इसका कारण आपराधिक न होकर ट्रंप की वह ढिठाई भी हो सकती है, जिसके लिए वह मशहूर रहे हैं, वरना ईरान वाले दस्तावेज को ही लें, तो इसे अपने पास रखने से भला ट्रंप को क्या मिल सकता था? इस पर भी शक है कि वह इसे किसी तरह इस्तेमाल कर सकते थे।

सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आवश्यक है धारा 124ए

अभिषेक सिंह
शोधार्थी विधि

भारत में राजद्रोह कानून 124ए को भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6 जो कि राज्य के विरूद्व अपराधों के विषय में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें राजद्रोह के बारे में कहा गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाने का प्रावधान है। स्पष्टीकरण प् अप्रीति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल है। स्पष्टीकरण प्प् घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करवाने की दृष्टि से टिप्पणी करना, इस धारा के तहत अपराधा नहीं है। स्पष्टीकरण प्प्प् घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रषासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष उत्पन्न करने के प्रयासों को ही राजद्रोह के रूप में दंडित करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए की व्याख्या स्पष्ट तौर से सरकार के उन उपायों या कार्यो की अस्वीकृति को बाहर करती है, जो घृणा, अवमान या असंतोष को उत्तेजित या उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करते है। आजादी के बाद संविधान सभा की चर्चा के बाद 1948 में राजद्रोह को हटा दिया गया था। संविधान सभा में कांग्रेस के नेता और षिक्षाविद् के एम मुंषी के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13 ;2द्ध में शामिल राजद्रोह शब्द को हटाने के लिए एक संषोधन प्रस्तुत किया, इस प्रकार राजद्रोह शब्द को संविधान से विलोपित कर दिया गया जब इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय अनुच्छेद 19;1द्ध;एद्ध ने भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। हालांकि उस दौरान भी भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के संबंध में धारा मौजूद थी। भारत के विधि आयोग की 279 वी रिपोर्ट के बाद फिर से राजद्रोह कानून के उपयोग चर्चा का विषय बन दिया है। आयोग ने रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के उपयोग से संबंधित आईपीसी की धारा 124ए में बदलाव के साथ इसे बनाए रखने की सिफारिष की है। धारा 124 ए जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है।स्पष्टीकरण प् अप्रीति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल है। स्पष्टीकरण प्प् घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करवाने की दृष्टि से टिप्पणी करना, इस धारा के तहत अपराधा नहीं है। स्पष्टीकरण प्प्प् घृणा, अवमान या अप्रीति को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रषासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण पअ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि धारा 124 ए से संबंधित कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानकी चाहिए जब तक कि एक पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं है प्रारंभिक जांच नहीं करता है और पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर इस दिखा में रिपोर्ट में कहा गया है कि एक परंतुक को शामिल करके दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 154 में एक संषोधन पेष किया जा सकता है।

स्वतंत्र भारत में राजद्रोह के मामले

तारा सिंह गोपी चंद बनाम स्टेट 1951 का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने वाले स्वतंत्र भारत में एक न्यायालय का पहला न्यायिक दृष्टांत था। चूंकि भारत अब एक स्वतंत्र गणराज्य था और स्वतंत्र भारत ने ब्रिटिष न्यायालयों द्वारा पारित दृष्टांतों पर संविधान सभा मे पारित संविधान की सर्वोच्चता को ग्रहण कर लिया था। इस मामले में तत्कालीन पंजाब उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 124 ए निर्विवाद रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, और इस आधार पर प्रावधान को अमान्य कर दिया कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। इस मामले के तुरंत बाद में 1951 में प्रधानमंत्री जवाहार लाल नेहरू की सरकार ने अनुच्छेद 19;1द्ध;एद्ध के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संविधान का पहला संषोधन पेष किया और अनुच्छेद 19;2द्ध को अधिनियमित किया ताकि राज्य को स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर उचित प्रतिबंध के रूप में राज्य की सुरक्षा को कम करने या राज्य को उखाड़ फेंकने के अविधिकपूर्ण कार्यो तक ही सीमित नहीं था, अब इसे राज्य के हित में भी होना था। सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती देने और विदेषी राज्यों के साथ संबंधों और इस संबंध में भाषण या अन्य किसी माध्यम से अपराध के लिए उकसाने पर नियंत्रण का नया आधार था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19;2द्ध देषद्रोह के बारे में तो कुछ नहीं कहता लेकिन राष्ट् की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा को खतरा होने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। सरकार उस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर सकती है। अब राजद्रोह के कानून का उद्देष्य केवल राज्य की सुरक्षा को खतरा व राज्य सरकार को उखाड़ फेकने के कार्यो तक ही सीमित नहीं था। अब इसे केवल राज्य की सुरक्षा के हित में होना था। इस तरह राजद्रोह के संबंध में व्यापक अर्थ वाले शब्दों ने राजद्रोह की धारा के उपयोग को अधिक विवेकषील व बुद्विमता उपयोग पर बल दिया गया। देबी सोरेन और अन्य बनाम राज्य 1954 में अब बोलने की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रस्तुत प्रथम संषोधन के बाद एक आदिवासी नेता ओ सरकार के खिलाफ भडकाफ भाषण के लिए हिरासत में लिया गया। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय में अस्वीकृति और असंतोष के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और कहा कि केवल असंतोष सार्वजनिक अव्यवस्था की और ले जाता है। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं मानते हुए भारतीय दंड संहित की धारा 124 ए की संवैधानिकता की भी पुष्टि की थी। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार 1962 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राजद्रोह की व्याख्या पर विषेष महत्व रखता है। इसे राजद्रोह के संदर्भ में सबसे अधिकारिक निर्णय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीषों की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इस कानून का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटनें के लिए नहीं किया जा सकता है। इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि विचाराधीन देषद्रोही भाषण से हिंसा को उकसाना या इसके कारण सार्वजनिक असंतोष फैले। चूंकि केदार नाथ ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी ना कि भारतीय राज्य की, और विवादित भाषण किसी भी तरह की हिंसा के लिए उकसाने वाला नहीं था इसलिए इसे देषद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वहीं हिंसा भड़काने की हानिकारक प्रवृति की उपस्थिति राजद्रोह की धारा को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त है। निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम राजा सम्राट 1942 में न्यायालय ने माना कि राजद्रोह को अनिवार्य रूप से मतलब है कि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने का इरादा या उसकी उचित मंषा, उसके शब्दों या कार्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हिंसा के लिए उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा राजद्रोह का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मामले के संबंध में यह माना गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया भाषण सरकार की आलोचना की कानूनी सीमा से अधिक नहीं था और इसलिए भारत का रक्षा अधिनियम 1939 के तहत राजद्रोह नहीं माना जा जा सकता था,लेकिन राजा सम्राट बनाम सदाषिव नारायण भालेराव 1947 में प्रिवी काउंसिल द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से अलग दृष्टि कोण रखा। केदारनाथ सिंह मामले को फिर से आधार मानते हुए बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाम राज्य 1995 में अभियुक्त पर राजद्रोह के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन एक स्वतंत्र सिंख बहुसंख्यक राज्य की मांग के पक्ष में नारेबाजी में शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीषों की खंडपीठ ने आरोपी के पक्ष में इस तर्क पर फैसला दिया कि विवादित भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और इससे वहां मौजूद भीड़ के मन में किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की संभावना नहीं थी बलवंत सिंह की कार्रवाई इसलिए देषद्रोह कीह श्रेणी में नहीं आती है। केदारनाथ सिंह के मामले में चर्चा किए हानिकारण प्रवृत्ति को यहां भी ध्यान में रखा गया इस तरह की प्रवृति को आक्षेपित भाषण के परिणामों को देखकर पता लगाया जाना चाहिए। धारा 124 ए को इंदिरा गांधी सरकार ने इतिहास में पहली बार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल कर 1974 में लागू हुई औपनिवेषिक काल की 1898 की दंड प्रकिया संहिता को निरस्त करने वाली नई दंड प्रक्रिया संहिता1973 में राजद्रोह को संज्ञेय अपराध बना दिया था। जिससे पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत किया गया। न्यायालयों ने हाल के दिनों में कुछ संषोधनों के साथ राजद्रोह के मामले में उपरोक्त व्याख्या पर भरोसा किया है। इस तरह का एक संषोधन लगभग एक दषक पहले अरूप भुईयां बनाम असम राज्य 2011 व श्री इंद्रा दा बनाम असम राज्य 2011 के मामलों में देखा गया था, दोनो ही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सात दिनों के भीतर सुनाए थे। दोनो निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह और निवारक निरोध के आरोपों पर निर्णय देते हुए ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियों के मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा आसन्न कानूनविहिन कार्रवाई के सिद्वांत परीक्षण पर भरोसा किया। इस परीक्षण के अनुसार सभी भाषण अमेरिकी संविधान के प्रथम संषोधन द्वारा संरक्षित है जब कि यह आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई को उकसाता नहीं है। एसजी वोमबाटकेरे बनाम भारत सरकार संघ 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यी खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता 1860 की विवादास्पद धारा 124 ए के क्रियांवयन पर रोक लगा दी थी। सभी लंबित परीक्षणों, अपीलों और कार्यवाही को स्थगित रखने के निर्णय पर पहुंची थी। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता भारत में बहस का विषय रहा है। आलोचकों का तर्क है कि कानून अस्पष्ट,व्यापक है और असहमति को दबाने और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए इसका दुरूपयोग किया जा सकता है, जो कि भारतीय संविधान द्वारा सुनिष्ति संरक्षित मौलिक अधिकार है। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक सिद्वांतों की रक्षा के लिए कानून को हटा दिया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के डर के बिना सरकार की आलोचना करने या अपनी राय व्यक्त करने के व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। राजद्रोह कानून के समथकों का तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए यह आवष्यक है। उनका तर्क है कि कानून राष्ट् विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है और देष को आंतरिक खतरों से बचाता है। अंतत राजद्रोह कानून को हटाने या बनाए रखने का निर्णय भारतीय विधायिका और न्यायपालिका के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, यह सुनिष्चित करना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवष्यक है। इन्हें देखते हुए ही विधि आयोग ने धारा 124 ए के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की सिफारिष की है।

दुर्घटनाएं क्यों नहीं रुक रहीं

सवाल पूछा जाएगा

प्रधानमंत्री जी ने रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया है। रेल मंत्री देश में नहीं हैं। प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय को भी देख रहे हैं। यह व्यवस्था अपने में संतोषजनक नहीं है, यह बात तो स्पष्ट है। इस दुर्घटना के कारण यह तथ्य और उजागर हो गया है कि सरकार में जिम्मेदारियों का जिस तरह से बंटवारा होना चाहिए था, वह नहीं है। आज यदि प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, तो देश उनसे यह आशा करता था और हम भी यह आशा करते थे कि वह दुर्घटना स्थल पर जाएंगे और जो हत और आहत हुए हैं, उनको शोक संवेदना देंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन जी गए हैं और उनकी रिपोर्ट अभी हमारे सामने नहीं है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि यह अब तक की हुई दुर्घटनाओं में से सबसे भयंकर दुर्घटना है। हो सकता है, इससे मिलती-जुलती और भी दुर्घटनाएं हुई हों। इस दुर्घटना के तीन पहलू हैं- एक तो तथ्यों का सवाल है कि वहां क्या हुआ? सरकार के वक्तव्य में इस पर प्रकाश डाला गया है, समाचारपत्रों में भी कुछ जानकारी है। एक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, दूसरी गाड़ी उससे आकर टकरा गई, लोग मर गए। मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। मैं इस पहलू को बाद में लूंगा कि संख्या के बारे में देश में और सदन में सरकार व विरोधी पक्ष के बीच में अलग-अलग आंकड़े क्यों दिए जाने चाहिए? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था। तथ्य अपनी जगह है, उन पर चर्चा होगी। किस छोटे कर्मचारी की गलती हुई, किस सिगनल मैन ने चूक की, एक गाड़ी खड़ी थी, तो उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई, यदि वह गाड़ी डेढ़ घंटे वहां खड़ी थी, तो क्या सूचना देना इतना कठिन था? इन तथ्यों पर बहस होती रहेगी, तथ्यों को उजागर किया भी जाना चाहिए, तथ्य जानना बहुत आवश्यक है।

लेकिन एक दूसरा पहलू है कि पिछले सालों में रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है, मैं गिनाना नहीं चाहता, समाचारपत्रों ने आज तिथि के अनुसार, वर्ष के अनुसार उन्हें उद्धृत किया है। 7 जनवरी, 1991 से लेकर, जब कलकत्ता में एक दुर्घटना हुई थी, 15-16 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हो सकता है कि यह सदन समाप्त हो, उससे पहले कोई भयंकर दुर्घटना और भी हो जाए! दुर्घटनाओं की संख्या क्यों बढ़ गई है, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए, इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

रेलवे दावा करता है और उस दावे को न मानने का कोई कारण नहीं है कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मैकनाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, सिगनलिंग की पद्धति बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए कदम उठाए गए हैं, मगर दुर्घटनाएं हो रही हैं... यहां पूरे रेलवे तंत्र का सवाल पैदा होता है। रेलवे को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, रेलवे द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए, उन सारे सवालों पर बहस जरूरी हो जाती है। जब दुर्घटना होती है, हम दो तरह की इन्क्वायरी करते हैं; कभी-कभी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होती है या रेलवे सेफ्टी के जो इंसपेक्टर हैं, वह जांच करते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। हमारी शिकायत है कि पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती, उसके 1-2 पैरे प्रकाशित कर दिए जाते हैं। सिफारिशों का क्या होता है, इसके बारे में सदन अनभिज्ञ है, देश को भी जानकारी नहीं है।...अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पूरे रेलवे सिस्टम पर एक प्रश्नचिह्न लग रहा है... क्या हम दुर्घटना नहीं रोक सकते? फिर हम किस प्रगति का दावा कर रहे हैं और रेलें सुरक्षा से चलें, यह बार-बार कहने का क्या अर्थ है? और यहां तंत्र का प्रश्न भी उठता है। लेकिन मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं, वह है अकांउटबिलिटी। दुर्घटना हो गई, 300 से ज्यादा लोग मर गए। पहले भी दुर्घटनाएं हुई थीं। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कुछ इस्तीफा नहीं देते। केवल मंत्री का सवाल नहीं है, मैं सरकार की अकांउटबिलिटी की बात कर रहा हूं। यह सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह रेलवे यात्रियों के प्रति उत्तरदायी है। अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो नैतिकता का तकाजा क्या है, यह सदन इसका उत्तर चाहता है? इसीलिए सरकार को कठघरे में खड़े करने की बात हो रही है। क्या सरकार जवाबदेह है? इन बढ़ती दुर्घटनाओं का उसके पास क्या उत्तर है? क्या वह अपने कर्तव्य के पालन में विफल नहीं रही है?

15 करोड़ छोटे किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती!

यूरोपीय आयोग के अनुसार, वर्ष 2020 तक व्यक्तिगत डेटा का मूल्य (सिर्फ एक वर्ग डेटा का) 1 लाख करोड़ यूरो तक हो गया है जो कि यूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8 प्रतिशत है। कोविड के बाद तो डेटा विश्व अर्थव्यवस्था का केन्द्र ही बन रहा हैं। बहुत से लोग डेटा को रुपये से अधिक मूल्यवान मानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि तेजी से विकसित हो रहे डेटा के उपयोग को देखते हुए अधिक से अधिक कंपनियां अपने या किसी और संगठन के डेटा पर अधिकार स्थापित करके अधिक से अधिक धन कमाने के लिए नित्य नए तरीकों को खोज रही हैं। यह नई अर्थव्यवस्था, भारत के 15 करोड छोटे किसानों और उनके परिवार वालों के लिए नया अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। डेटा उपयोग से भारतीय किसानों को सही तरीके से बाजार, सूचना, वित्त और कृषि-लागत और सेवाओं के बेहतर संबंध के साथ ही साथ सही फसल उगाने में भी मदद कर रहा है। इसके विपरीत, यह 15 करोड़ छोटे किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अवैतनिक डेटा मजदूर में भी बदल सकता हैं। ये कंपनिया फिर कसानों को ही दी जाने वाली सेवाआ और उत्पादों को बेचने के लिए अपने इसी डेटा की वजह से मूल्य वृद्धि कर लेंगी। साथ ही साथ संरक्षणवाद भी स्थानीय किसानों को वैश्विक ज्ञान और सेवाओं से बाहर कर सकती है। यह स्थिति एक स्वैच्छिक और न्यायोचित फार्म डेटा प्रमाणन मानक के विकास की मांग करती है जो किसान संबंधी डेटा के उत्पादन और व्यापार के सामाजिक और आर्थिक निरन्तरता के सिद्धांत पर आधारित हों। डेटा दुनिया में वैचारिक विमर्श का हिस्सा बनती जा रही है। कई मंचों पर एक वैचारिक ढांचा बनाने के उद्देश्य से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जैसे 'कच्चे माल के रूप में डेटा एक नया ईंधन हैं जिन्हें एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से निकालने और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही राजनीतिक-तर्कसंगतता समाज को बड़ी कंपनियों के निष्कर्षण प्रयासों का प्राकृतिक लाभार्थी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती हैं यह ठीक वैसे ही जैसे कभी 'उपनिवेशवाद' को एक ÷सभ्यता परियोजना÷ के रूप में पेश किया गया था! आज एक भारतीय किसान को अपने डेटा पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे वे अपने द्वारा उत्पादित फसलों का नियंत्रण नहीं रखते और लाभ नहीं ले पाते हैं। यदि किसान बड़ी कंपनियों को भविष्य में अपना विस्तृत कृषि लेखा-जोखा प्रदान नहीं करते हैं तो वे उच्च-मूल्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर होने का जोखिम उठाते हैं। भारतीय किसान आज अपने व्यक्तिगत डेटा के साथ-साथ खेती की जानकारीए जैसे कि फसल विवरण, खेती के तरीके, लागत उपयोग, कीट.विवरण खर्चे का लेखा-जोखा और उत्पाद संबंधी आँकड़ें विभिन्न व्यवसायों को मुफ्त प्रदान करते हैं। किसान, ÷सेवा शर्तें÷ और सहमति प्रपत्र जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं, जो उनकी समझ से बाहर होता है और जिनमें कंपनियों द्वारा अजीबो गरीब दावे बढ़ चढ़कर किए होते है, बाद में उनके डेटा का क्या होता है, इसके बारे में किसान कुछ भी नहीं जानते हैं। यह डेटा इन कंपनियों के लिए, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक लाभ पहुंचाता है जो रसायनों को बढ़ावा देने और नई रासायनिक जरूरतों की पहचान करने में सक्षम सिद्ध होता है और इसलिए संबंधित अनुसंधान और विकास में संभावित निवेश को बढ़ाने में भी उपयोगी होता है। खाद्य कंपनियां भी खरीद लागत कम करने, कीमतें निर्धारित करने, जोखिम कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए किसानों के डेटा का उपयोग करती हैं।सुपर मार्केट किसानों के पर्यावरणीय डेटा का उपयोग यूरोपीय बाजारों में भारी कार्बन कर से बचने के लिए और अपने नैतिक उपभोक्ताओं को सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की अपील करने के लिए करता है। ऐसा करके यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्वयं को सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनी के रूप में स्थापित करते हैं। इस बारे में उचित चिंताएं उठती है कि कृषि डेटा का मालिक कौन है और बड़े व्यवसायों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का स्वामित्व किसके पास है, जो इसे अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल देता है। क्या उपग्रहों, ड्रोन, सेंसर और किसानों के मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा गोपनीयता संबंधी सवाल खड़े करते हैं? बेशक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि डेटा का आर्थिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है और इसका उचित हिस्सा किसानों तक कैसे पहुंचता है? भारत में ऐसी कोई प्रभावी स्वैच्छिक या अनिवार्य संरचना नहीं है जो यह सुनिश्चित करें कि छोटे किसानों के लिए डेटा अर्थव्यवस्था न्यायसंगत और समावेशी हो। इसलिए डेटा के उचित रख-रखाव और एक समावेशी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु न्यायोचित फार्म डेटा के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणन मानक की आवश्यकता है।

सुप्रिया को अहम जिम्मेदारी

एनसीपी चीफ शरद पवार ने आखिर पार्टी में दो नए कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा करके नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। शनिवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य का प्रभारी भी बनाया। कहने को प्रफुल्ल पटेल भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो पवार परिवार के नहीं हैं। लेकिन यहां दो बातें गौर करने लायक हैं। एक तो यह कि पटेल को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पार्टी की कोई मजबूत मौजूदगी नहीं है।दूसरी बात यह कि सुप्रिया सुले को पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की कमान भी दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि शनिवार को लिए गए फैसलों के जरिए पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले को सबसे अहम भूमिका सौंपी है। इन्हीं फैसलों का दूसरा और उतना ही अहम पक्ष यह है कि पवार के भतीजे और हाल तक उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे अजित पवार को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण पद उनके पास पहले से है और पार्टी के महाराष्ट्र से जुड़े मामलों में सबसे मजबूत आवाज भी उन्हीं की मानी जाती है। लेकिन अब सुप्रिया सुले के महाराष्ट्र प्रभारी बनने के बाद इन मामलों में भी उन्हें सुले को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा।निश्चित रूप से यह उनके लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। पार्टी में जो नई हायरार्की बनी है, उसमें सुप्रिया सुले का दर्जा स्पष्ट रूप से अजित पवार से ऊपर हो गया है। इसके बावजूद अजित पवार ने किसी तरह के असंतोष या नाराजगी के संकेत नहीं दिए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कम से कम तत्काल उनकी तरफ से इस फैसले को कोई चुनौती नहीं दी जाने वाली। इससे महीने भर पहले चली उस कवायद की भी सार्थकता साबित होती है, जो शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के रूप में सामने आई और फिर नेताओं, कार्यकर्ताओं के दबाव में उसे वापस लेने के साथ समाप्त हुई थी। उस कवायद ने पार्टी पर सीनियर पवार की पकड़ को फिर से इतना मजबूत बना दिया कि वह बगैर किसी आशंका के इन बड़े फैसलों की घोषणा कर सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता कि पार्टी में अजित पवार कमजोर पड़ गए हैं। राज्य में आज भी संगठन पर उनका दबदबा कायम है। पार्टी का भविष्य और महाराष्ट्र में काफी हद तक विपक्ष का प्रदर्शन भी इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रिया सुले को पार्टी ने जो भूमिका सौंपी है, उसे वह कितनी कुशलता से अंजाम दे पाती हैं और इस क्रम में अजित पवार से उनका कितना और कैसा तालमेल बन पाता है।

अब यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर रक्षा मंत्री की दो टूक...

नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दो टूक अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। जो कि वैश्विक संगठन की नैतिक वैधता को कमजोर करता है। यह जानकारी रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर सेना द्वारा राजधानी में आयोजित की गई एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान कार्यक्रम में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प भी मौजूद थे। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, सेनाप्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा अताशे भी मौजूद थे।

- बोले राजनाथ सिंह, बड़ी आबादी वाले देश को स्थायी सीट ना देना संगठन की नैतिक वैधता पर लगाता सवालिया निशान।

यूएन निकायों को बनाया जाए लोकतांत्रिक

रक्षा मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के निकायों को अधिक लोकतांत्रिक, वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधि बनाया जाए। जब हम अतीत को याद करते हैं तो हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। पूरे संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र को देखना भी महत्वपूर्ण है और इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों को दुनिया की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के प्रति अधिक चिंतनशील बनाना है।

स्थायी सदस्यता की राह में रोड़े अटकाता ड्रैगन

गौरतलब है कि वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल दो साल का होता है। भारत भी सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रहा है और उसने पिछले साल दिसंबर महीने में अपना कार्यकाल पूरा किया है। भारत बीते लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हर बार परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों में से एक यानी चीन द्वारा उसके इस प्रस्ताव को वीटो शक्ति के इस्तेमाल के जरिए रोक दिया जाता है। जबकि परिषद के बाकी चार अन्य वीटो पावर वाले देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में हैं।

1945 में हुई सुरक्षा परिषद की स्थापना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जिसमें तत्कालीन भारत भी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ था। परिषद पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और यूएन में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। यहां बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के तमाम शांति अभियानों में भारतीय सेना की भागीदारी कुल करीब ढाई लाख से अधिक है। सेना के 5 हजार 300 कर्मी यूएन के आठ मिशन में तैनात हैं। भारत यूएन के अभियानों में भागीदारों करने वाला तीसरा सबसे बड़ा भागीदार देश है। यूएन चार्टर के तहत दुनियाभर में जारी संघर्षों के बीच शांति स्थापना के प्रयासों में लगे 159 भारतीय सैनिक अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं।

खबर संक्षेप

प्लांट स्टीम लाइन में विस्फोट से 19 घायल

अनुगुल। ओडिशा में रेल दुर्घटना के बाद एक और हादसा हो गया। यहां ढेंकनाल जिले के मेरामंडली

स्थित टाटा स्टील प्लांट में मंगलवार को दोपहर एक बजे बड़ा हादसा हो गया। यहां ब्लास्ट फर्नेस की स्टीम लाइन फट गई, जिसमें 19 श्रमिक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई, वहीं गंभीर रूप से घायल सभी श्रमिकों को कटक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंपनी में स्टीम लाइन विस्फोट में 19 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

चीन-रूस की दोस्ती से चौकन्ना हुआ भारत

वॉशिंगटन। अमेरिका और भारत अपने सैन्य संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

अमेरिका दौरे पर कई बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें सैन्य हार्डवेयरों के सह-उत्पादन से लेकर लड़ाकू जेट टेक्नोलॉजी में भागीदारी जैसे बड़े हथियार सौदे शामिल हैं। अमेरिका ने इस तरह से रक्षा सौदे सिर्फ चुनिंदा देशों के साथ ही किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की इस हफ्ते नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक संभावित रक्षा रोड मैप को तैयार किया है। इसका अर्थ है।

भारत ने निकाली चीन की हेकड़ी

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा

डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत टॉप पायदान पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से साल 2022 में रिकॉर्ड संख्या में डिजिटल पेमेंट किए गए। इस दौरान करीब 89.5 मिलियन डिजिटल लेनदेन हुए हैं। भारत टॉप-5 लिस्ट में बाकी चार देशों से कहीं आगे है। माय गोव इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 46 फीसद रियल टाइम पेमेंट किए गए। इस लिस्ट में ब्राजील दूसरे पायदान पर है। ब्राजील में 29.2 मिलियन डिजिटल पेमेंट हुए। जबकि चीन का तीसरा स्थान है।

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लताड़ा

नई दिल्ली। आज के समय में ज्यादातर लोग ई-कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ई-कॉमर्स

साइट्स का इस्तेमाल खरीदारी या दूसरी तरह की कोई भी शॉपिंग के लिए किया जाने लगा है। जैसे-जैसे समय के साथ खरीदारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे ई-कॉमर्स में धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ई-कॉमर्स को लेकर ग्राहकों की शिकायतों का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त चेतावनी दी।

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे पर सियासी संग्राम

विपक्षी नेताओं ने घेरा, सरकार ने डोर्सी के बयानों को 'झूठा' बताकर किया खारिज

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक बयान से भारत का राजनीति पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों के सरकार को घेरने पर सरकार ने डोर्सी के दावे को खारिज किया है। मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि भारत में जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ विदेशी ताकतें देश को अस्थिर और बदनाम करने के लिए सक्रिय होते हैं।

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के हालिया इंटरव्यू के बाद देश में राजनीति हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार को निशाने पर लिया है। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक बयान से भारत का राजनीति पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। दूसरी ओर सरकार ने जैक डोर्सी के दावे को खारिज किया है। किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने ट्विवर को बंद करने की धमकी दी थी। कांग्रेस, आप, सपा, टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। डोर्सी ने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग प्वाइंट्स को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के समय ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में कहा, भारत में जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ विदेशी ताकतें और यहां उनके एजेंट एक योजनाबद्ध तरीके से देश को अस्थिर और बदनाम करने के लिए सक्रिय होते हैं। उन्होंने दावा किया कि जैक डोर्सी सफेद झूठ बोल रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि डोर्सी के समय ट्विटर प्रशासन को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा, कोई जेल नहीं गया और ना ही ट्विटर बंद किया गया। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, डोर्सी और उनकी टीम ने 2020 से 2022 तक बार-बार कानूनों की अवमानना की और जून 2022 में ही उन्होंने आखिरकार अनुपालन शुरू किया। उन्होंने कहा, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि उसके कानूनों का भारत में संचालित सभी कंपनियां पालन करें। चंद्रशेखर ने कहा, जनवरी 2021 में प्रदर्शनों के दौरान अनेक दुष्प्रचार किए गए और यहां तक कि नरसंहार की खबरें थीं जो कि निश्चित रूप से फर्जी थीं।

भाजपा ने केवल तानाशाही की टूलकिट अपनाई -खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस के राजनैतिक वंशज जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिन्दुस्तानियों के खिलाफ खडे होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े वो ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग न रचे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ' अंग्रेजों की गुलामी से भाजपा ने केवल तानाशाही की टूलकिट अपनाई है। खरगे ने कुछ प्वाइंट भी मंगलवार (13 जून) को ट्वीट किए। उन्होंने कहा,'किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया।

केजरीवाल व टीएमसी ने भी दी प्रतिक्रिया

ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर देश के अंदर किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। मामले पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ट्वीट करते हुए कहा, अनुरोध या इस मामले में छिपी हुई धमकी! जैक डोर्सी के हालिया एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे बीजेपी सरकार की ओर से किसानों के विरोध और सरकार की आलोचना करने वालों के एकाउंट के ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी।

भारत हमारे लिए बड़ा बाजार -डोर्सी

पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने सोमवार को यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जैक डोर्सी से 'ताक़तवर लोगों' की मांगों के संबंध में सवाल पूछा गया था। इस सवाल में जवाब में उन्होंने भारत का नाम लेते हुए किसान आंदोलन के समय की कहानी बताई। इंटरव्यू में जैक डोर्सी से पूछा गया, दुनियाभर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगें करते हैं, आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? इस सवाल के जवाब में जैक डोर्सी ने कहा, मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है, जहाँ से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगें आ रहीं थीं। कुछ खास पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके अकाउंट बंद करने के बारे में हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है। आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया। हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दौरा

जेक सुलिवन की एनएसए अजित डोभाल से हुई मुलाकात

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन अपने समकक्ष अजित डोभाल के न्योते पर दो दिवसीय भारत के आधिकारिक दौरे आए। उनके साथ अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों एनएसए एक व्यापक द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर व्यापक चर्चा में नियमित रूप से लगे हुए हैं।

सीईटी के लिए नई प्राथमिकताओं के लिए अवसर

जेक सुलिवन की वर्तमान यात्रा इस प्रकार दो एनएसए के लिए अब तक की प्रगति की समीक्षा करने और सीईटी के लिए नई प्राथमिकताएं और उद्देश्य निर्धारित करने का अवसर प्रदान करेगी।

24 घंटे में मारे गए 7 आतंकी

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दो और आतंकी किए ढेर

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों को मिली जानकारी के बाद एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें 4 आतंकवादी ढेर हुए। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने यहां मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है।

आतंकियों से एके-47 व हथियार मिले

कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादी तुफैल सहित एलईटी के दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले बारामूला जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर

रक्षा मंत्री सिंह 'आईएनएस विक्रांत' पर करेंगे योग

कविता जोशी ▶▶ नई दिल्ली

अगले सप्ताह 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत 'आईएनएस विक्रांत' पर योग करेंगे। जिसमें उनके साथ सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के तमाम शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह दूसरा ऐसा मौका होगा जब रक्षा मंत्री किसी विमानवाहक युद्धपोत पर योगासन करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वर्ष 2019 में उन्होंने गोवा में भारत के एक अन्य विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर योग किया था। वहीं इस बार योग दिवस के दौरान विक्रांत केरल में तैनाती पर रहेगा। जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

2014 में हुई योग दिवस की शुरुआत

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मोदी के इस प्रस्ताव को तीन महीने के भीतर पूर्ण बहुमत से पारित किया। यह यूएन में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को मंजूरी दी गई।

इस वर्ष योग दिवस की थीम

इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग रखी गई है। भारत के अलावा 21 जून को दुनियाभर के तमाम देशों में योग किया जाएगा। आर्कटिक से अंटार्कटिका तक के क्षेत्र में भी योगाभ्यास किया जाएगा। जिसमें प्राइम मेरिडियन लाइन पर या उसके आसपास के देश भी योगाभ्यास में शामिल होंगे। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में भी योग अभ्यास होगा। हिमाद्रि-स्वालबार्ड, आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र और भारती, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अनुसंधान केंद्र में भी दुनियाभर के लाखों अन्य लोगों के साथ इस उत्सव में शामिल होने की संभावना है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के फ्लाइट डेक भी तालमेल दिखाते हुए योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे।

गृह मंत्रालय का एक्शन

एनजीओ केयर इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस रद्द

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए एनजीओ केयर इंडिया के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन को लेकर यह कड़ा कदम उठाया है। एनजीओ केयर इंटरनेशनल कंडरेशन का हिस्सा है, जो पिछले 70 वर्षों से गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बहिष्कार जैसे उद्देश्यों के साथ भारत में काम कर रहा है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनजीओ को अपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने के लिए नोटिस दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केयर इंडिया, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, मलाला फंड और यूएसएआईडी जैसे भागीदारों के साथ काम करती है, उसने निलंबन नोटिस की पुष्टि की।

भारतीय मूल के ड्राइवर से बातचीत कर जानी स्थिति

राहुल गांधी ने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक उठाया ट्रक के सफर का लुत्फ

एजेंसी ▶▶ न्यूयार्क

राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता के सवाल के जवाब में ड्राइवर बताता है कि वो ट्रक चलाकर करीब 8 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं। राहुल गांधी 10 दिनों के लिए अमेरिका यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने भारतीय ड्राइवर तजिंदर सिंह से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में ट्रक को ड्राइवर को कम्फर्ट को देखकर तैयार किया गया है, लेकिन हिन्दुस्तान में जो ट्रक हैं उसको ड्राइवर के कम्फर्ट से कुछ लेना-देना नहीं है।

यहां खुद के ट्रक नहीं होते, दूसरों के ही चलाते हैं

भारतीय ड्राइवर ने अमेरिका और हिन्दुस्तान के ड्राइवरों में फर्क को बताते हुए कहा कि यहां यानी अमेरिका में ड्राइवर अच्छे पैसे कमा लेते हैं और सर्वाइव भी कर जाते हैं लेकिन इंडिया में ड्राइवरों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. भारत में अधिकतर ड्राइवर के पास खुद की ट्रक नहीं होती है वो दूसरों की ही ट्रक चलाते हैं।

अमेरिका जाने से पहले ट्रक से किया था शिमला का सफर

अमेरिका दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी भारत में भी ट्रक की सवारी की थी। राहुल गांधी दिल्ली में ट्रक में सवार हुए थे और शिमला तक का सफर किया था. सफर के दौरान राहुल गांधी ड्राइवर से बात कर ड्राइवरी के दौरान होने वाली परेशानियां के संबंध में बात भी की थी।

दूरसंचार कंपनियां गोपनीयता के मुद्दों को लेकर सतर्क

एआई फिल्टर से लगेगी अनचाही कॉल्स पर लगाम, कंपनियों को 30 दिन का अल्टीमेटम

कंपनियों को एआई फिल्टर का इस्तेमाल करना होगा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

जल्द ही आपको अनचाही और स्पैम कॉल्स से छुटकारा मिलने वाला है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। टेलिकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर एआई फिल्टर लगाने होंगे. इसके साथ ही कंपनियों को अनचाही कॉल का डाटा भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना पड़ेगा। ट्राई ने अनाउंसमेंट की थी कि 1 मई 2023 से टेलिकॉम कंपनियों को एआई फिल्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये फैसला बढ़ते स्पैम कॉल्स और स्कैम्स को रोकने के लिए किया गया था।

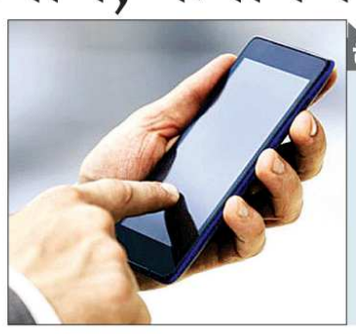

कैसे काम करेगा एआई फिल्टर?

एआई फिल्टर की मदद से ऐडवरटाईजिंग वाले फोन कॉल और प्रमोशनल मैसेज की पहचान होगी। इसके बाद ऐसे नंबरों को ब्लॉक किया जाएगा। इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों के ली कॉलर आईडी फीचर देना होगा। इसके जरिए कॉल करने वाला नंबर स्पैम है या नहीं इसका पता लग जाएगा। नए नियमों के अनुसार 10 अंकों वाले ऐसे नंबर जो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वह बंद कर दिए जाएंगे।

स्पैम कॉल्स पूरी तरह से नहीं रुकी

इस बीच जियो और एयरटेल ने फोन कॉल्स में एआई फिल्टर लगाने के लिए हामी भी भरी थी। हालांकि नियम लागू करने के बाद भी स्पैम कॉल्स पूरी तरह से नहीं रुकी हैं। नियमों को ठीक से लागू करवाने के लिए ट्राई

स्क्रीन पर दिख जाएगी फोटो

एआई फिल्टर के साथ, नियामक प्राधिकरण ने 10-अंकीय नंबरों पर प्रमोशन कॉल्स को प्रतिबंधित करने के साथ ट्राई की एक कॉलर आईडी सुविधा शुरू करने की योजना है जो कॉल आने के समय कॉलर का नाम और फोटो स्क्रीन पर दिखाएगी। हालांकि, दूरसंचार कंपनियां गोपनीयता के मुद्दों को लेकर सतर्क हैं रहने के साथ कॉलर आईडी फीचर के कार्यान्वयन के संबंध में टूकॉलर के साथ चर्चा कर रही हैं। एक उद्योग निकाय सीओएआई ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) के अनिवार्य कार्यान्वयन का विरोध करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए वैकल्पिक बनाने का अनुरोध किया। एसोसिएशन ने शामिल लागतों के संबंध में चिंताओं का हवाला देते हुए ट्राई के साथ एक तकनीकी, गोपनीयता और नियामक रिपोर्ट दायर की गई।

गुजरात की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय

मुंबई-भुज-राजकोट में 5 की मौत; कच्छ-सौराष्ट्र में तट से 10 किमी तक का इलाका खाली कराया जाएगा

पोरबंदर (एजेंसी)।

अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किमी/घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उससे पहले अच्छी बात यह है कि तूफान कुछ कमजोर हुआ है। हालांकि यह अब भी खतरनाक ही है।

तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी-बारिश का दौर जारी है, जिसमें पांच लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के तटीय जिलों- कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मोरबी के तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 7500 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। कच्छ-सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गांवों के 23 हजार लोगों को आज से शिफ्ट किया जाएगा। उधर, अमित शाह ने आज दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की।

गुजरात के द्वारका से 290 किमी दूर है तूफान

मौसम विभाग के मंगलवार सुबह 9 बजे के अपडेट के मुताबिक, तूफान 8 किमी/घंटे की स्पीड से नॉर्थ-वेस्ट में आगे बढ़ रहा है। तूफान मंगलवार सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 300 किमी, द्वारका से 290 किमी, जखौ पोर्ट से 340 किमी, नालिया से 350 किमी दूर था। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ-नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ेगा।

राजस्थान के 12 जिलों में तूफान बिपरजॉय का खतरा

गुजरात जाने वाली ट्रेनें कैंसिल, अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट

चमकता राजस्थान, जयपुर। अरब सागर में बने तूफान (चक्रवात) बिपरजॉय का असर राजस्थान में 15 जून से दिखने लगेगा। राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में इस तूफान के कारण बारिश देखने को मिल सकती है।कुल 12 जिलों में इसका खतरा बना रहेगा। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से गुजरात के पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम जाने वाली वाली एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के संचालन को आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 14 जून की शाम या 15 जून की सुबह ये चक्रवात गुजरात और पाकिस्तान से टकराएगा। तट से टकराने के बाद ये चक्रवात गुजरात के हिस्सों में डीप डिप्रेशन और राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में लो-प्रेशर एरिया के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके असर से इन एरिया में एक-दो दिन भारी बारिश होगी। इस चक्रवात से राजस्थान में नुकसान होने की आशंका बहुत कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान तक पहुंचने तक इस चक्रवात की हवाओं की स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन मोइश्चर लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण दो दिन कई जगहों पर भारी बारिश (60 से लेकर 100रू तक) बारिश दर्ज हो सकती है।

16-17 को सबसे ज्यादा असर

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 जून को इस सिस्टम असर से आंधी बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद ही शुरू हो जाएगी। जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में 16 जून को कहीं-कहीं भारी

बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति 45 से 55 चरू प्रतिघंटा तक दर्ज हो सकती है। 17 जून को भी इस सिस्टम का असर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग कुछ भागों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में दिखेगा असर

इस चक्रवात का असर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में देखने को मिलेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

तूफान से ट्रेनों का संचालन रूका

चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के तटीय जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और यहां भारी से अतिभारी बारिश होने की आशंका जताते हुए यहां 100 से 130चरूकी स्पीड से तूफान आने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए उत्तर पश्चिम और उत्तर रेलवे जोन ने गुजरात जाने वाली एक दर्जन ट्रेनों का संचालन को आंशिक और पूर्ण रद्द करने का निर्णय किया है।

महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाना दो पायलट को पड़ा महंगा, एयर इंडिया ने दोनों को किया रोस्टर से आउट

नई दिल्ली (एजेंसी)। अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में आमंत्रित करने पर एयर इंडिया के एक पायलट को उड़ान भरने से रोके जाने के एक महीने बाद फिर ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है। दरअसल, एयरलाइन ने पिछले सप्ताह दिल्ली-लेह उड़ान के कॉकपिट में एक महिला को आमंत्रित करने के मामले में अब दो पायलटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

दो पायलट को एयर इंडिया ने किया ऑफ रोस्टर

विमान के कॉकपिट में एक अनधिकृत महिला यात्री के प्रवेश करने के संबंध में केबिन क्रू से शिकायत मिलने के तुरंत बाद एयर इंडिया प्रबंधन ने पायलट और सह-पायलट के खिलाफ कार्रवाई की। एयर इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, पायलट की एक महिला मित्र ने नियमों का पालन किए बिना कॉकपिट में प्रवेश किया, दोनों पायलटों को एयर इंडिया द्वारा ग्राउंड/ऑफ-रोस्टर कर दिया गया है।

जांच के लिए बनाई गई समिति

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, डीजीसीए इस मुद्दे से अवगत है और इस मामले में प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, एयर इंडिया की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक अधिकारी ने बताया, एयर इंडिया ने इस मामले की विस्तार से जांच के लिए एक समिति बनाई है।

लेह के लिए कुशल पायलट को होता है चयन

लेह मार्ग सुरक्षा के लिहाज से देश के सबसे कठिन और संवेदनशील हवाई मार्गों में से एक है और एक वाणिज्यिक विमान में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में अनुमति देना कानून का उल्लंघन है।

पत्नी के सामने सुसाइड की कोशिश

धमकाया- 'मैं तो मरुंगा, तुम्हें भी मरवाऊंगा' और काट ली हाथ की नसें

चमकता राजस्थान, जयपुर। जयपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की आंखों के सामने सुसाइड की कोशिश की। उसने अपने हाथ की नसें ब्लेड से काट डाली।

धमकाया- मैं तो मरुंगा और तुम्हें भी मरवाऊंगा: गंभीर हालत में उसे स्रू हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मानसरोवर थाने में पत्नी ने पति के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया है। ASI कालूराम ने बताया कि गोपालपुरा बाईपास मानसरोवर निवासी 33 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसमें बताया गया कि करीब 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ससुराल में झगड़ा होने पर कुछ दिन साथ रहने के बाद वो पीहर आ गई।

पति भी आकर उसके साथ पीहर में ही रहने लगा। आपसी सुलह के बाद करीब 6 महीने से किराए का मकान लेकर पति के साथ जयपुर में ही रहने लगी। कुछ दिनों बाद पति ने घर खर्च देना भी बंद कर दिया। शराब पीकर मारपीट करने लगा। परेशान होकर वह 10 जून को सुबह करीब 8.30 बजे वह अपने घर (पीहर) आ गई। पीछे-पीछे पति अपनी मां, बहन-भाई को लेकर पीहर आया और गाली-गलौज कर मारपीट करने की कोशिश की। जाते-जाते धमकी देता हुआ गया कि तुझे शाम को बताता हूं। शाम करीब 7:30 बजे शराब के नशे में पति घर आया। हाथ में ब्लेड लेकर जान से मारने की धमकी देकर वार किया। महिला ने खुद का बचाव करते हुए पुलिस को बुलाने की बात कही। ये सुनकर पति ने ब्लेड से खुद के हाथ की नसें काट ली।

पांच मेजर मिनरल ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर 21 जून तक नीलामी

जयपुर, (कासं)। प्रदेश के निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया है कि राज्य के उदयपुर, चित्तोडगढ़, सीकर, जयपुर के पांच मेजर मिनरल ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ई नीलामी की इस प्रक्रिया में निविदादाता 21 जून तक बोली लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उदयपुर के हरियाव जसपुरा के 94.62 हैक्टयर क्षेत्रफल के लाइम स्टोन के ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी की जा रही है।

हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर की ड्यूटी, वेतन विसंगति को लेकर नाराजगी

जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक ने जताया विरोध

चमकता राजस्थान, अजमेर। पुलिस और जेल विभाग कर्मचारियों में वेतन विसंगति को लेकर जेल कार्मिकों का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों के द्वारा मंगलवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जेल कार्मिकों ने विरोध जताते हुए कहा कि 7 दिनों तक काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए सभी कार्मिक अपना विरोध करेंगे। अगर इसके बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल कर अपना काम करते हुए विरोध जाहिर करेंगे। हाई सिक्योरिटी जेल में मंगलवार से जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक सभी ड्यूटी पर रहकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती हैं तो उसके बाद आगे की कार्यकारिणी तय होगी। मंगलवार सुबह हाई सिक्योरिटी और सेंट्रल जेल में जेल कार्मिकों ने इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर

किया। जेल कार्मिक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों में वेतन विसंगति के साथ-साथ कार्मिकों को मिलने वाले भत्ते व अन्य सुविधाओं में भी अंतर है। पदोन्नति को लेकर भी कई बिंदुओं पर आपत्ति है। जनवरी में हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके जल्द मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, इसके प्रस्ताव बनाकर जब वित्त विभाग को भेजा तो पहली बार में उसे निरस्त कर दिया गया और दोबारा भेजा गया प्रस्ताव आज तक लंबित है। जेल कार्मिकों ने कहा कि 1998 से पहले राजस्थान पुलिस और जेल कार्मिकों का वेतन समान होता था। कुछ दिनों पहले गृह सचिव का बयान जारी हुआ था कि राजस्थान के जेल कार्मिकों के लिए दिल्ली मॉडल जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र, एमपी और यूपी में लगभग सभी स्टेट्स में पुलिस और जेल कार्मिकों का वेतन और भत्ता समान है, लेकिन राजस्थान के जेल कार्मिकों का नहीं है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।

जयपुर डिस्कॉम- एमनेस्टी योजना का 61 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ

जयपुर, (कासं)। सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा जनवरी माह में लागू की गई एमनेस्टी योजना का मई माह तक 61 हजार 606 उपभाक्ताओं ने लाभ उठाया है। जयपुर डिस्कॉम ने इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर देय 31 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए के ब्याज व पेनल्टी की छूट प्रदान की है और इससे डिस्कॉम को 130 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। योजना 30 सितम्बर, 2023 तक लागू रहेगी और इस दौरान मूल बकाया राशि जमा कराने पर उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2022 तक कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शन के 21649 उपभोक्ताओं द्वारा 64 करोड़ 63 लाख 39 हजार रुपए की राशि जमा करवाकर 16 करोड़ 24 लाख 56 हजार रुपए के ब्याज व पेनल्टी की छूट का लाभ प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के 31 दिसम्बर, 2022 तक के 39957 डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर 14 करोड़ 81 लाख 94 हजार रुपए के विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज राशि की छूट का लाभ प्राप्त किया हैं और इनसे डिस्कॉम को 65 करोड़ 90 लाख 46 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। कुमावत ने बताया कि सभी अभियन्ताओं को निर्देश प्रदान कर दिए हैं कि डीसी (डिसकनेक्टेड कन्ज्यूमर) व पीडीसी (परमानेंट डिसकनेक्टेड कन्ज्यूमर) उपभोक्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर बकाया राशि की वसूली के कार्य में तेजी लाएं और आगामी 6 माह में इस तरह के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर संभागीय मुख्य अभियन्ता के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं एवं उनको निर्देशित किया गया है कि जांच के दौरान बिजली चोरी मिले तो वीसीआर भर कर जुर्माना राशि के साथ ही पूर्व की बकाया राशि की भी की वसूली की जाए।

खेत पर आवास के लिए 50 लाख रूपये तक का मिलेगा ऋण

जयपुर, (कासं)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसान को खेत पर आवास पर निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। इस योजना में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रूपये तक का ऋण तीन किश्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसान को 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि (15 वर्ष) का होगा। गुहा सोमवार को अपेक्स बैंक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंहगाई राहत कैम्प में आवेदनकर्ताओं के प्राप्त पात्र आवेदनों को शीघ्र ही ऋण वितरण किया जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया जाना है। अभी तक 2.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए है, उन्होंने निर्देश दिए कि राजीविका से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।

आर्ट कैम्प में जुटे प्रदेशभर के 50 से अधिक चित्रकार

कैनवास पर शुरू किया चित्र बनाना, पहली बार राजस्थान ललित कला अकादमी ने दिया मंच

जयपुर, (कासं)। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से सोमवार से राज्य स्तरीय कैम्प की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक , पद्मशाकिर अली, कलाविद् सुब्रतों मंडल और अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार ने कैनवास पर पेंट करते हुए किया। अकादमी के उप चेयरमैन डॉ मूलाराम गहलोत, सचिव डॉ रजनीश हर्ष व कला शिविर संयोजक अमित हारित सहित अकादमी के सदस्यों ने कलाकारों का स्वागत किया। राजस्थान ललित कला अकादमी के चेयरमैन मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने जानकारी देते हुए बताया सोमवार से राजस्थान राज्य के विभिन्न शहरों और गांव के 50 कलाकारो का चित्रकला शिविर शुरू हुआ है । सका उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक ,

पद्मशाकिर अली, कलाविद् सुब्रतों मंडल और अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार ने कैनवास पर पेंट करते हुए किया।

सका उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक , शाकिर अली, कलाविद् सुब्रतों मंडल और अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार ने कैनवास पर पेंट करते हुए किया।

इस युवा चित्रकार प्रोत्साहन कला शिविर में जयपुर सहित उदयपुर, अजमेर, अलवर, चितौड़गढ़, टोक, पाली, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड, किशनगढ़, वनस्थली, सीकर, जोधपुर, दौसा, सरदार शहर, राजगढ, बूंदी सवाईमाधोपुर आदि जगहों के कलाकारों शामिल हुए है । तीन दिन तक कलाकार अकादमी परिसर में रह कर लाइव पेंट करेंगे ।

ये कलाकार हुए शामिल : इसमें कृष्ण कुंडारा, विजय कुमावत, सुरेन्द्र सिंह, दिलीप डामोर, राम खिलाड़ी सैनी, श्रीकृष्ण महर्षि, सुमन जोशी, अजय मिश्रा, विकास मीणा, किर्ति सिंह, शिखा कुमारी, करुणा, अनुप्रिया राजावत, वर्षा झाला, दिव्या चौहान, ईरा टाक भाग ले रहे है। अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास ने बताया कि कला शिविर के आयोजन के पीछे मुख्य उदेश्य ऐसे कलाकारों को सामने लाना है, जो कि विगत वर्षों में हाशिये पर रहे हैं और श्रेष्ठ सृजन कार्य होने पर भी जिनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाई। इस शिविर में अधिकांश कलाकार युवा हैं और वे हैं जिन्हें अकादमी के किसी आर्ट कैम्प में भाग नहीं लिया है। कला शिविर के संयोजक अमित हारित ने बताया कि सभी कलाकारों की अपनी विशिष्ट शैली है, जिसे वे तीन दिवसीय कला शिविर में रूप प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने चिमनपुरा में नवीन कृषि महाविद्यालय की दी स्वीकृति

जयपुर, (कासं)। जयपुर जिले के चिमनपुरा में बाबा नारायण दास राजकीय कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह महाविद्यालय निर्माणाधीन भवन में पृथक से संचालित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाविद्यालय खोलने व संचालन के लिए 29 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चिमनपुरा में अभी बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य, विज्ञान तथा कृषि संकाय संचालित थे, जिसमें से कृषि संकाय को बंद करके बाबा नारायण दास कृषि महाविद्यालय खोला जा रहा है। वहीं, चिमनपुरा में पहले से कला संकाय में संचालित बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय में स्वीकृत पदों को बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय में हस्तांतरित करते हुए इस महाविद्यालय में वाणिज्य, विज्ञान एवं कला संकाय का संचालन किया जाएगा।

जल के अपव्यय को रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी - महंत भगवानदास

कौशल गौशाला जाम्बा में ओरण आरती कार्यक्रम के पोस्टर का हुआ विमोचन

बाप/कविकान्त खत्री/चमकता राजस्थान

बाप ब्लॉक के कोशलनगर में संचालित कौशल गौशाला में ओरण आरती परिक्रमा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए गौशाला संचालक व आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक महंत भगवानदास ने कहा कि धरती पर पीने योग्य पानी मात्र 3 फीसदी ही है। पानी के अपव्यय को रोकना पुण्य का काम है। कई देशों में पानी की कमी के कारण घरो के जल नल कनेक्सन काटे गए। वहां नहाने पर प्रतिबंध है। ऐसी स्थति हमारे यहां नही आये, इसलिए पानी सहेजकर रखे। उन्होने कहां की जल के बिना हमारा कल सुरक्षित नहीं है। घरो के नलों से टपकने वाले पानी को बन्द करने, कार व गाड़ी प्रतिदिन धोने की आदत में बदलाव लाने, घर के आंगन को सूखे पोचे से साफ करने, बगीचे में कम पानी का उपयोग करने की हिदायत देते हुए महंत ने कहा की हम सब मिलकर पानी के आने वाले संकट को रोकने में योगदान करे।हमारी छोटी पहल से आने वाले सूखे में पानी बचाने का पुण्य होगा। धरती पर गाय से बढ़कर कोई तीर्थ नही है। उसकी सेवा से सकुन मिलता है। हमे पेड़ लगाने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए। एक पेड़ चार आदमी को जिंदा रख सकता है। पेड़ो की कटाई बहुत चिंता की बात है।तुलसी, पीपल, नीम, बरगद दुसरो के मुकाबले ज्यादा आक्सीजन देते है।उन्होने बारिश के बाद एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। महन्त ने बताया की गौशाला परिसर में इस समय 40 हजार विभिन्न किस्म के पौधे लहलहा रहे है। इस वर्ष 5 हजार पौधे ओर जनसहयोग से लगाने का लक्ष्य है। पेड़ पौधों से ग्रह, नक्षत्र के बुरे प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए केवल वेद लक्षणा गो माता ही है। 27 जून को कोलू पाबूजी मे आयोजित होने वाले एतिहासिक कार्यक्रम ओरण आरती महोत्सव के बैनर का विमोचन भी किया गया। इस मौके संत ओमप्रकाश, महेश्वरी समाज बाप अध्यक्ष अशोक चाण्डक, सीमाजन कल्याण समिति जिला अध्यक्ष अखेराज खत्री, गो सेवक जगदीश चाण्डक, विजय कुमावत, पशुधन सहायक महिपाल विश्नोई, डूंगर राम, मालाराम फुलानी, जगदीश बिश्नोई, बंसी पंवार आदि उपस्थित थे।

डोटासरा बोले- बीजेपी में मनभेद, वसुंधरा-पूनिया प्रदर्शन में क्यों नहीं

कहा...परोपकारी महिला नाथी बाई का अपमान कर रहे बीजेपी नेता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री

चमकता राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि 25 हजार बुलाए थे और 2500 भी नहीं आए। बीजेपी की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी थीं। आज के प्रदर्शन में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का मौजूद रहना यह साबित करता है कि इनके मतभेद ही नहीं मनभेद हैं। बीजेपी किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक नहीं हो पाई। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नाथी का बाड़ा तक ईडी पहुंचने के राजेंद्र राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा- ईडी अपराधियों तक जाए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। नाथी बाई एक समाजसेवा ब्राह्मण परोपकारी महिला थीं,वे सबकी मदद करती थी। किसी से मदद के बदले कुछ नहीं लेती थी। ऐसी भली महिला का बार-बार गलत अर्थों में नाम लेकर उसका अपमान किया जा रहा है। ऐसी महिला जिसको हम सम्मान से नाम लेते हैं, उसका अपमान किया जा रहा है। अब ये जुमलेबाजी कर रहे हैं बाकी इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष

बीजेपी के 200 मुख्यमंत्री बताने के आरोप पर डोटारसरा ने कहा कि वे कम बता रहे हैं। हमारे यहां तो हर जिस कार्यकर्ता ने सरकार बनाने में भूमिका निभाई वह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष की तरह ही है। बीजेपी की तरह दो या तीन लोग ही सत्ता पर काबिज नहीं होते, कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है।

बीजेपी के मंच पर एक भी ओबीसी नेता को बोलने नहीं दिया

डोटासरा ने कहा- बीजेपी किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक नहीं हो पाई। आज के प्रदर्शन से वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के नहीं होने से साबित होता है इनके मतभेद नहीं मनभेद हैं। आज जितने भी वक्ता थे उनमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी के हितैषी होने का राग अलापने वाली बीजेपी ने किसी ओबीसी नेता को बोलने का मौका तक नहीं दिया। राजेंद्र राठौड़ भाषण दे रहे थे जो 500 लोग भी नहीं थे। इनकी दुर्गति देखिए,कार्यकर्ताओं को भाषण सुनाने के लिए कसमें दिलाई जा रही थी। बीजेपी के नेताओं में इतने मनभेद हैं कि एक नहीं हो सकते। स

बीजेपी का ईडी का मुद्दा ही खत्म हो गया

डोटासरा ने कहा- कर्नाटक की हार से बौखला कर बीजेपी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सरकार पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। ये डेढ़ साल से एक ही राग अलाप रहे हैं कि ईडी आएगी। अब तो ईडी आ गई। ईडी जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। जो दोषी होगा जिसने अपराध किया होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी उस पर कार्रवाई हो जाएगी।

अब तो मोदी का चेहरा भी फीका पड़ गया

डोटासरा ने कहा- बीजेपी के नेता एकजुट नहीं हैं। मोदीजी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, अब मोदीजी का चेहरा भी फीका पड़ गया। मोदी के चेहरे पर न पंजाब जीत पाए न कर्नाटक। आरएसएस ने भी कह दिया कि अब मोदी के भाषणों या मन की बात से और मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं

डोटासरा ने कहा-योजना भवन में केश और गोल्ड मिलने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें दोषी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो गई। बीजेपी राज में माइनिंग घोटाला हुआ था, उसमें हमने आंदोलन किया तब जाकर अफासर को सस्पैंड किया था। बीजेपी राज में जो घोटाले हुए उसमें आज के बीजेपी के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही नेताओं की तरफ उंगली उठाकर साजिश रच रहे हैं। उनको पॉलिटिकली टारगेट करक मुद्दे उठाकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कह रहे हैं कि 2013 में आईटी विभाग में घोटाले हो रहे हैं। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी।

डीआरएम से जवाब मांगा : जयपुर-उदयपुर स्टेशन व रूट की ट्रेन में अव्यवस्थाएं, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया

चमकता राजस्थान, जयपुर। हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए अजमेर व जयपुर डीआरएम से जवाब मांगा है। मामला जयपुर व उदयपुर रेलवे स्टेशन सहित उदयपुर जाने वाली ट्रेन में अव्यवस्थाओं का है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय कर उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा है कि वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या रेलवे मजिस्ट्रेट से इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी लें। यह निर्देश जस्टिस सुदेश बंसल ने दिया है। दरअसल, जस्टिस बंसल 12 जून को सुबह 6ः15 की ट्रेन से उदयपुर गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि जयपुर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर अनियंत्रित निजी वाहनों के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। निजी वाहनों को स्टेशन बिल्डिंग के नजदीक जाने की छूट होने और इन्हें नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। ट्रेन में बैठने की सीट, टॉयलेट और गेट का भी उचित रखरखाव नहीं था। उदयपुर के राणा प्रताप स्टेशन पहुंचने पर जस्टिस बंसल को वेटिंग हॉल बंद मिला, वहां मेंटेनेंस रजिस्टर भी नहीं था। स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी बंद था। स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। स्टेशन पर एरिया ऑफिसर व उच्चाधिकारियों के संपर्क नंबर तक नहीं थे। ऐसे में जस्टिस बंसल ने पाया कि इन सुविधाओं को प्राप्त करना यात्रियों का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें यहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

तवर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त

बाप/कविकान्त खत्री/चमकता राजस्थान

बाप निवासी मुरलीधर तंवर को अखिल भारतीय दर्जी महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय दर्जी महासभा के लिखमाराम परिहार ने बताया कि राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय अनुसार बाप निवासी मुरलीधर तंवर को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तंवर को नवीन दायित्व की जिम्मेदारी सौंपते हुए समाज हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तवे के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर समाज बंधुओं सहित आमजन ने खुशी व्यक्त की है।

पातावत ने किया क्षेत्र का दौरा

बाप/कविकान्त खत्री/चमकता राजस्थान

राजपूत महासभा फलोदी के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी कुंभसिंह पातावत बाप क्षेत्र के दौरे पर रहे। बाप में शिक्षक नेता टीकमचंद पालीवाल की पुत्री के विवाह समारोह में पातावत ने शिरकत करते हुए नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, समाजसेवी अखेराज खत्री, कांग्रेस नेता नंदकिशोर तंवर, देवीलाल पालीवाल, विजय कुमावत, दीपक पालीवाल, रामस्वरूप, चैनसुख, मदन गोपाल शर्मा, रामनारायण पालीवाल, छगनलाल आदि उपस्थित थे।

भोपाल-इंदौर-जम्मूतवी की ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव

आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पर सिग्नल अपग्रेड के कारण जयपुर पहुंचने में होगी देरी

चमकता राजस्थान, जयपुर। जयपुर में आसलपुर जोबनेर स्टेशन के बीच रेलवे की ओर से सिग्नल अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते कल जयपुर से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ये गाड़ियां भोपाल, इंदौर, जम्मू तवी और अजमेर के लिए संचालित होंगी। ऐसे में, जयपुर स्टेशन पहुंचने में इन ट्रेनों को 1 से डेढ़ घंटे की देरी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 12466 जोधपुर-इंदौर गाड़ी 15 जून को जोधपुर से चलेगी। फुलेरा स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने के बाद इस गाड़ी को एक घंटा स्टॉपेज देकर रवाना किया जाएगा। इसी तरह गाड़ी संख्या 14645, जैसलमेर-जम्मूतवी ट्रेन 14 जून को जैसलमेर से चलेगी और फुलेरा स्टेशन पर आकर 55 मिनट का स्टॉपेज देगी। गाड़ी संख्या 19712 भोपाल-जयपुर पैसेंजर 14 जून को फुलेरा स्टेशन पर 1 घंटे 30 मिनट स्टॉपेज देने के बाद जयपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09605 अजमेर-जयपुर एक्सप्रेस 15 जून को अजमेर से अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट देरी से चलेगी।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अभय सिंह चौहान के लिए किरण प्रिंटर्स, किरण प्रिंटर्स के लिऐ एमबी प्रिंटर्स, सी- 74 सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित एवं 141 ए, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, राधा गोविन्द पथ, श्याम नगर, सोडाला, जिला-जयपुर (राजस्थान)-302019 से प्रकाशित। सम्पादक: अभय सिंह चौहान, मोबाइल: 9314505000 (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)

जनभागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

रंगोली प्रतियोगिता में छात्राध्यापकों ने दिखाया उत्साह

चमकता राजस्थान

चित्तौड़गढ़/गंगरार, 13 जून, 2023(अमित कुमार चेचानी)। शिक्षा संकाय, मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा भारत के सम्मान में जी 20 की अध्यक्षता के संदर्भ में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' के निर्देश पर 'जनभागीदारी कार्यक्रम' के अंतर्गत 'रंगोली' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मेवाड़ कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, गंगरार के छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं ने प्राध्यापिका डॉ किरण त्रिपाठी के संयोजन में 'जी 20'' के संदर्भ में विश्व एक परिवार होने के संदेश पर केन्द्रित रंगोली बनाने में उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्राचार्य डॉ. अरुणा दुबे ने छात्राध्यापकों को 'जी 20' के संबंध में कलाकौशल के साथ रंगोली बनाने सम्बंधी मार्गदर्शन किया। इसके बाद निर्णायक मंडल द्वारा अवलोकन कर परिणाम घोषित किया गया। प्राध्यापिका मंजु चाष्टा ने निर्णायकों का आभार व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विद्या जटिया एवं सुमन गहलोत, द्वितीय स्थान मस्तीराम एवं निशा प्रजापत तथा तृतीय स्थान सुमन कंवर चौहान एवं मोनिका श्रीवास्तव के ग्रुप ने प्राप्त किया।

आंदोलन की राह पकड़ कर मुद्दों का हल करवाया जाएगा - किसान नेता अंगद सिंह

चमकता राजस्थान

चमकता राजस्थान ब्यूरो चीफ दीपचंद शर्मा भरतपुर, किसान मजदूर विद्यार्थी यूनियन (अंगद) की अर्धवार्षिक मीटिंग पुष्प वाटिका कॉलोनी स्थित शारदा एकेडमी में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ नरेंद्र सिंह फौजदार की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर जीवन लाल शर्मा एवं भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आजाद खेम सिंह ने की। मीटिंग में मुख्य तौर पर 11 मांगों के ऊपर चर्चा की गई जिनमें इआरसीपी नहर परियोजना भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र में पेंडिंग आरक्षण, ई रिक्शा चालकों का भरतपुर में पुलिसिया दबंगई से मुक्ति और उनके लिए मूलभूत सुविधाओं सहित एक ई रिक्शा स्टैंड का निर्माण जैसे आधारभूत मुद्दों के साथ महाराजा सूरजमल जी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करवाने पूरे राजस्थान में किसानों के कृषि बिजली बिल हमेशा के लिए माफ करने, भरतपुर में किसान छात्रावास का निर्माण, पुष्प वाटिका कॉलोनी में एनएच 21 से चिकसाना रोड तक के लिंक मार्ग को किसान मार्ग नाम दिए जाने, मंडियों में पल्लेदारों के लिए विश्राम स्थल, वाटर कूलर आदि का निर्माण जैसे मुख्य मुद्दों पर सरकार एवं प्रशासन से कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे लोकप्रिय बाल किसान नेता अंगद सिंह ने अपने उद्बोधन में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की प्रवाह करें और उनको अच्छे संस्कार देकर देश समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर नागरिक बनने का मार्ग प्रशस्त करें। गौरतलब है कि इस मीटिंग में पिछले दिनों पुलिस से इलेक्ट्रिक रिक्शा चालकों की हुए विवाद पर भी संवाद हुआ और भरतपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आईपीएस श्याम सिंह की तारीफ की गई जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा चालकों के हितों की रक्षा के लिए यूनियन के द्वारा उठाए गए कदम को तुरंत संज्ञान लेकर उनकी मदद की और आगे के लिए यह तय किया गया कि इलेक्ट्रिक रिक्शा यूनियन के योग्य लोगों को किसान मजदूर विद्यार्थी यूनियन (अंगद)के इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रकोष्ठ बनाकर उनको आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे एवं रिक्शा पर संगठन की नेम प्लेट जारी की जाएगी।

बाल किसान नेता अंगद सिंह ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लगता है फिर से आंदोलन की राह पकड़कर ही इन मुद्दों का हल करवाया जाएगा। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आजाद खेम सिंह फौजदार ने कहा कि किसान और जवान की मौजूदा हालातों को बदलने के लिए आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है जिसमें किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद निश्चित पेंशन बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दे देश के आधारभूत हालातों में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं।

नगर निगम टीमों का दबदबा, ग्राम पचायतों की टीम धराशाही वार्ड-12 ने वार्ड-31 को 9 विकेट से हराया

धौरमई को वार्ड-47 ने 8 विकेट से हराया

चमकता राजस्थान

चमकता राजस्थान ब्यूरो चीफ दीपचंद शर्मा भरतपुर, खेलो इण्डिया के खेल महोत्सव-2023 के अन्तर्गत भरतपुर शहर के लोहागढ स्टेडियम पर संयोजक यश अग्रवाल के सनिध्य में 5 जून से आयोजित हो रही भरतपुर विधानसभा स्तरीय टी-10 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार 13 जून को नगर निगम के वार्ड टीमों का बल्लेबाज खिलाडियों का दबदबा रहा,जिन्होंने छक्के और चौक्के लगाकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की वाही-वाही लूटी और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 6 जून से आज तक हुए सभी मैचों में बल्लेबाज खिलाडियों ने 1092 छक्के तथा 1848 चौक्के लगाए, वहीं गेंदबाज खिलाडियों ने 672 विकेट झटके। ग्राम पंचायतो की टीमों ने 302 एंव नगर निगम के वार्ड की टीमों ने 786 छक्के तथा ग्राम पंचायत की टीमों ने 998 एंव नगर निगम वार्ड की टीमों ने 850 चौक्के लगाए। छक्के लगाने में नगर निगम वार्ड टीमें एंव चौक्के लगाने में ग्राम पंचायतों की टीमें अव्वल रहीं, जबकि विकेट लेने में नगर निगम वार्ड टीमें अव्वल रहीं। नगर निगम वार्ड टीमों के गेंदबाज खिलाडियों 366 एंव ग्राम पंचायतों की टीम के गेंदबाज खिलाडियों ने 306 झटके। खेलो इण्डिया के संयोजक यश अग्रवाल ने बताया कि शहर के लोहागढ स्टेडियम में मंगलवार को खेले गये टी-10 क्रिकेट का पहला मैच नगर निगम वार्ड-50 एंव वार्ड-64 मध्य खेला गया, जिस मैच मे वार्ड-64 को वार्ड-50 ने 48 रन से हराया। इस मैच में पुष्पेन्द्र सिंह ने सर्वाधिक 56 रन बनाकर मैन ऑफ दा मैच का खिताब हासिल किया है। दूसरा मैच ग्राम पंचायत धौरमई एंव वार्ड-47 के मध्य हुआ, जिस मैच में वार्ड-47 ने 8 विकेट से धौरमई को हरा दिया और इस मैच के ऑल राउंडर खिलाडी हनी शर्मा मैन ऑफ दा मैच रहे। तीसरा मैच वार्ड-48 एंव वार्ड-34 के मध्य खेला गया, जिस मैच में वार्ड-34 को वार्ड-48 ने 5 विकेट से पराजित कर दिया और इस मैच के ऑल राउंडर खिलाडी संजय सुनारी मैन ऑफ दा मैच रहे। चौथा मैच वार्ड-12 एंव वार्ड-31 के मध्य खेला गया जिस मैच में वार्ड-12 ने वार्ड-31 को 9 विकेट से हराया। इस मैच के मुकाबले में ऑल राउंडर खिलाडी शान्तनु मदेरणा मैन ऑफ दा मैच रहे। पाचवां मैच ग्राम पंचायत बरसो एंव वार्ड-05 के मध्य खेला गया जिस मैच में वार्ड-05 ने ग्राम पंचायत बरसों को 8 विकेट से हरा कर जीत हासिल की। मैच का मैन ऑफ दा मैच खिताब बल्लेबाज विक्रम चौधरी ने हासिल ने किया जिन्होनें 29 रन बनाए।

अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड में भरतपुर टीम की लगातार दूसरी जीत

कार्तिक,सौरभ और अवदेश चमके

चमकता राजस्थान

चमकता राजस्थान ब्यूरो चीफ दीपचंद शर्मा भरतपुर, राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित की जा रही अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता में भरतपुर की टीम ने बूंदी जिले की टीम के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज की जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि जयपुर के अरावली क्रिकेट मैदान पर खेले गए मुकाबले में भरतपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में कार्तिक शर्मा 153 और सौरभ गोदारा 109 की शतकीय पारियों की बदौलत 403 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया मैच के दूसरे दिन बूंदी की टीम के खिलाफ अवदेश खटाना ने 4 विकेट चेतन शर्मा ने 2 और सौरभ गोदारा ने 2 विकेट लिए इस गेंदबाजी के सामने 365 रनों पर बूंदी की टीम सिमट गई और भरतपुर की टीम ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत दर्ज की। भरतपुर का अगला दो दिवसीय मैच दौसा के खिलाफ 15 और 16 जून को जयपुर में खेला जाएगा इस मौके पर जिला संघ अध्यक्ष अरुण सिंह और जिला कोच और मैनेजर मौनू रौतवार खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए साथ में मौजूद थे इस जीत पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी उपाध्यक्ष विष्णु लोहिया और राजेश शर्मा कोषाध्यक्ष मुनेंद्र तिवारी संयुक्त सचिव राकेश मित्तल जिला संघ के सदस्य नाहर सिंह पेगौर, बीनू जगीना, मनोज कुमार शर्मा, राजेश गुप्ता एवं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव चीनिया तथा संघ के चयनकर्ता नरेश खत्री,सूरज शर्मा लंकेश सियाराम,प्रेम सिंह आदि ने संघ के कार्यालय पर मिठाइयां बांटी और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

प्रथम वार्षिकोत्सव स्वामी श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ आयोजित।

चमकता राजस्थान

जयपुर-श्री श्याम खाटू वाले की समिति जयपुर के तत्वाधान में 10 जून 2023 को सायंकाल 4:15 से भजनामृत सत्संग समुराई पीकॉक गार्डन, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, जयपुर में स्वामी श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज हाथोज धाम एवं महंत मोहन दास जी महाराज पुजारी निज मंदिर खाटू श्याम के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू अग्रवाल पार्षद जयपुर ग्रेटर, वार्ड नंबर 64 रहें।

समिति के पदाधिकारी संजय गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, विनोद हरितवाल, रामकिशन, प्रिया मोदी, ब्रजभूषण ने बताया कि इस अवसर बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार कर भव्य झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में विख्यात भजन गायक कलाकार कुमार गिरिराज, राजू मेहरा, पूजा सखी (पटियाला) राज राठौड़, मनोज शर्मा सहित अनेक जाने-माने भजन कलाकारों ने अपने प्रस्तुति प्रस्तुत कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया।

समिति द्वारा आए हुए अतिथियों का माला, साफा, पहनाकर भगवान का विग्रह चित्र भेंट स्वरूप प्रदान किया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि उपज मंडी बाड़ी में 15/6/2023 समय दोपहर 12 बजे आमसभा को करेंगे सम्बोधित

चमकता राजस्थान

धौलपुर (रामदास तरुण ब्यूरो चीफ) जिला धौलपुर के बाड़ी उपखंड में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि उपज मंडी बाड़ी में 15 /6/2023 समय दोपहर 12 बजे आमसभा को संबोधित करेंगे। जिसकी तैयारी के लिए बाड़ी विधायक माननीय गिर्राज सिंह मलिंगा जी, कांग्रेस ब्लांक अध्यक्ष निजामुद्दीन, पूर्व कांग्रेस ब्लांक अध्यक्ष मोहम्मद शकील कुरैशी, मुस्ताक अहमद,दीपू कुशवाह, नासिर पार्षद प्रतिनिधि, इस्माइल पार्षद प्रतिनिधि, ने बाड़ी के लुहार पाडा, चंगवरियापाडा, कुरैशी पाडा संतराशपाडा,हथियापोल मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आभान किया। बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने दावा किया है कि रैली ऐतिहासिक होगी।

14 जून को यहां लगेंगे मंहगाई राहत कैंप

चमकता राजस्थान

भरतपुर, (राजवीर सिंह)मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में भारी उत्साह है। महंगाई राहत कैम्पों के अन्तर्गत 14 जून को उपखण्ड भरतपुर के ग्राम पंचायत घुस्यारी एवं तुहिया, उपखण्ड कुम्हेर की ग्राम पंचायत सैंत व तमरेर, उपखण्ड डीग की ग्राम पंचायत दिदावली, उपखण्ड कामां की ग्राम पंचायत खेडली गुमानी एवं कनवाडा, उपखण्ड नगर की ग्राम पंचायत मानौता कलां, उपखण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत सांवलेर, उपखण्ड नदबई की ग्राम पंचायत परसवारा, उपखण्ड भुसावर की ग्राम पंचायत बारौली, उपखण्ड वैर की ग्राम पंचायत रायपुर, उपखण्ड बयाना की ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली एवं उपखण्ड रूपवास की ग्राम पंचायत निभेरा व जोतरोली में प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि नगर निगम भरतपुर के वार्ड संख्या 16 व 17 चौधरी मैरिज होम में, कुम्हेर के वार्ड संख्या 19 के अम्बेडकर भवन हेलक गेट कुम्हेर, नदबई के वार्ड संख्या 33, 34, 35 अग्निशमन कार्यालय में, डीग में वार्ड नम्बर 28, 29 कार्यालय नगरपालिका डीग में, नगर में वार्ड नम्बर 3, 4 सीकरी रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में, सीकरी के वार्ड संख्या 13 सैनी चौपाल कुन्डा बास का वास में, कामां के वार्ड संख्या 31, 32 गांधी पार्क भवन में, बयाना में वार्ड नम्बर 28 अग्रवाल धर्मशाला शिव गंज मण्डी में, वैर में वार्ड संख्या 20 भरतपुर गेट स्थित नवीन स्कूल में, भुसावर के वार्ड संख्या 19 कार्यालय नगरपालिका में, रूपवास के वार्ड संख्या 14 नगरपालिका कार्यालय रूपवास में एवं उच्चैन के वार्ड संख्या 21 खरका के सरपंच हाउस में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

रक्तदान करें.... ताकि रक्त के अभाव में कोई नहीं हो अलविदा: रोहित मंगल

चमकता राजस्थान

धौलपुर (रामदास तरुण ब्यूरो चीफ) जिला धौलपुर में दोस्तो जैसा कि आप जानते है जिस तरीके से जीवन में हर दान का अपना अलग महत्व होता है, वही रक्त दान का सर्वोच्च दान है। क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। जिंदा रहना स्वस्थ रहना.... रक्तदान करना सिर्फ यही बाकी नहीं कि अपने रक्त का दान किया है।

रक्तदान का अर्थ होता है किसी परिवार की उम्मीदों का दान, किसी की खुशियो का दान.......

जीवन में पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन जो चीज सिर्फ निर्मित मानव शरीर से है उसे आप कैसे खरीदोगे, यहां आकर इंसान का पैसा, जुगाड़ सब कुछ जार जाता है। जब बच्चा 18 साल का होता है। तब परिवार वाले उसे बताते है। कि आप अब वोटर हो गए आप मतदान कर सकते हो लेकिन उसे वहां अगर ये भी समझाया जाए कि आप देश हित के लिए मतदान करने योग्य हो गए तो मानवता हित के लिए रक्तदान योग्य भी हो गए, आप किसी को जीवन दे सकते हो, आप किसी को वो खुशिया दे सकते जिसके लिए वो अपना जीवन जी रहा है,

आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर संकल्प लें और रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ाए....खुद डोनेशन करें। बच्चो से भी करवाये जागरूक बने आपके एक रक्त दान से तीन लोगो की जान बचाई जाती है।

रक्तदान के लिए क्या है जरूरी

1. ब्लड प्रैशर सामान्य होना चाहिए।
2. उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. रक्तदाता का वजन 50 किलो से अधिक होना चहिए।
3. हीमोग्लोबिन का स्तर 4. 12 ग्राम से अधिक होना चाहिए।
5. रक्तदान किए हुए व्यक्ति को कम से कम 3 महीने हुए हो

कुछ विशेष प्रकार की 6. बीमारी से पहले कभी या वर्तमान में ग्रस्त ना हो

रक्तदान करने से लाभ

ब्लड डोनेशन से हार्ट अटैक की आशंका कम हो जाती है। डॉक्टर्स का मानना है कि डोनेशन से खून पतला होता है, जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। - एक नई रिसर्च के मुताबिक नियमित ब्लड डोनेट करने से कैंसर व दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर करता है।

संगीत ग्रुप द्वारा धौलपुर शहर मे कार्यक्रम किया आयोजित

चमकता राजस्थान

धौलपुर (रामदास तरुण ब्यूरो चीफ) धौलपुर जिले में गीत गाता चल ग्रुप के द्वारा संगीत प्रेमियों ने एक संगीत संध्या का आयोजन किया। यह आयोजन सैपऊ रोड स्थित होटल इम्पीरियल मे किया गया। जिस कार्यक्रम मे बाड़ी-धौलपुर-मुरैना और बसेड़ी के विभिन्न संगीत प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान करीब 30 कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के नए पुराने गाने और भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया कार्यक्रम का उदेद्श्य आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी मे तनावमुक्त रहने तथा वर्तमान की संगीत की कला धीरे धीरे प्रचलन से दूर होती जा रही है इसको लोगो के दिलो मे जिंदा बनाए रखने हेतु आयोजन किया गया। संगीत संध्या मे लोगो ने जमकर लुत्फ़ उठाया।

इस कार्यक्रम के दौरान धौलपुर शहर से उत्तम गोयल, संतोष सक्सेना, मनमोहन मथुरिया, योगेश शर्मा, शिवांश मंगल, अजय ममता सक्सेना, रजनी गोयल ,भास्कर, सूर्यांशु, योगेश मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप मे मिस्टर एंड मिसेज डॉ. बी. डी. जिंदल,मिस्टर एंड मिसेज डॉ. नीरज गोयल ,योगेश। मुरैना से मिस्टर एंड मिसेज राजेंद्र,बसेड़ी से मिस्टर एंड मिसेज अंकुर,बाड़ी से डॉ. निरमा, हरिओम, राजकुमार, राजीव, अनुज, अमित, योगेश दीपक, नीरज साथ ही छोटे कलाकारों में हिमांशु और प्रखर ने भाग लिया।

प्रेमसिंह को शिविर में मिला आवसीय पट्टा

चमकता राजस्थान

भुसावर,(राजवीर सिंह) पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नैवाडा निवासी प्रेमसिंह पुत्र प्रतापसिंह ने बताया कि मैं ग्राम आबादी मे लम्बे समय से निवासरत हूं परन्तु मेरे पास आबादी की जमीन व मकान का कोई पटटा या दस्तावेज नही था। आज मैंने ग्राम पंचायत नैवाडा मुख्यालय पर आयोजित प्रशासन गांवो के संग व महंगाई राहत कैम्प में आवासीय पटटा बनवाने हेतु आवेदन किया जिस पर कार्यवाही करते हुए ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासन ने 150 वर्ग गज क्षेत्रफल का आवासीय भूमि का पटटा जारी किया। इससे मुझे मेरे आवास का मालिकाना हक भी मिल गया। इस कार्यवाही व सुगम प्रक्रिया से मैं खुश हूँ। राज्य सरकार व प्रशासन के द्वारा आयोजित कैम्प में किये जा रहे कार्य प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। मैं राज्य सरकार एवं प्रशासन की प्रशंसा करता हूं।

विधायक सुरेश टांक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया आभार प्रकट

चमकता राजस्थान

किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक द्वारा छात्र-छात्राओ के उज्जवल शैक्षणिक भविष्य के दृष्टिगत की गई अनुशंसा एवं सतत प्रयासों से किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक किशनगढ़ की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खण्ड़ाच हुई सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा आदेश जारी करने पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य सरकार का आभार प्रकट कियाराजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खण्ड़ाच के क्रमोन्नत होने से ग्राम पंचायत डींडवाडा एवं इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो के छात्र- छात्राओ को अब स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगा उच्च माध्यमिक शिक्षा का लाभ, इसी के साथ इस विद्यालय में सृजित होंगे विभिन्न प्राध्यापको, अध्यापकों के साथ प्रधानाचार्य का भी पद तथा विद्यालय में सुविधाओ के विस्तार के साथ ही संचालित होगा विद्यालय में शाला विकास एवं प्रबंधन समिति तथा ग्रामीणों साईं प्राप्त कर कला संकाय मे नव क्रमोन्नत स्कूल में विषयों का चयन किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ग्राम में विधायक सुरेश ताकि अथक प्रयासों से स्कूल खुलने पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई एवं ग्राम वासियों ने विधायक का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अवगत कराया कि शीघ्र ही उनका स्वागत अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

बसेड़ी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी होतम सिंह जाटव ने 3 दर्जन से अधिक गांवों का किया दौरा।

चमकता राजस्थान

धौलपुर (रामदास तरुण ब्यूरो चीफ) बसेड़ी विधानसभा संभावित प्रत्याशी होतम सिंह जाटव ने मंगलवार को नवलपुरा,रामफल का पुरा,भागीरथ का पुरा,भवनपुरा,जटपुरा,अंगद का पुरा, सलेमपुर,नौनेरा,पीपरी का पुरा,ममोधन,भगौरा,अतरसूमा,जारगा,सांगौरी,नागौरी,दनकटा,कटैलपुरा, बसेड़ी,खिडौरा, गोटे का पुरा,मासुक का पुरा सहित 3 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर 15 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बाड़ी में होने वाली आम सभा के पीले चावल देकर निमंत्रण दिया और लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की इस दौरान बसेड़ी विधानसभा संभावित प्रत्याशी होतम सिंह जाटव, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, विनोद कुमार शर्मा, सुरजीत गुर्जर, मुकेश कोली,बंटी चैंची सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

ईवीएम एवं वीवीपैट डिमोस्ट्रेशन केन्द्र का फीता काटकर किया शुभारम्भ

मताधिकार का प्रयोग कर सरकार में निभायें अपनी भागीदारी - लोकबंधु

चमकता राजस्थान

भरतपुर,(राजवीर सिंह)जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने कलैक्ट्रेट परिसर में ईवीएम एवं वीवीपैट डिमोस्ट्रेशन केन्द्र का फीता काटकर शुभारम्भ किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस केन्द्र के माध्यम से ईवीएम एवं वीवीपैट के संदर्भ में फैली भ्रांतियाँ दूर होंगी, इसके साथ ही आमजन में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन के संचालन के प्रति जागरूकता भी आयेगी। उन्होंने समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे समस्त स्तरों पर होने वाले निर्वाचनों में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

इस अवसर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन को निर्भीक, निष्पक्ष, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भेदभाव एवं प्रलोभन रहित मतदान करने के संबंध में शपथ दिलाई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन रतन कुमार, स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्रीमती बीना महावर, सहायक जिला कलक्टर भारती भारद्वाज, सहायक नोडल अधिकारी स्वीप ओमप्रकाश खूटेला सहित जिला कलैक्ट्रेट परिसर के अधिकारी, कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

समाज के भामाशाह गरीब एवं दिव्यांगजनों की मदद के लिए आयें आगे - लोकबंधु

जिला कलेक्टर ने दिव्यांग दुरब सिंह को सौंपी ऑटो रिक्शा की चाबी

चमकता राजस्थान

भरतपुर,(राजवीर सिंह)तहसील रूपवास के ग्राम रामपुरा निवासी दिव्यांग दुरब सिंह को स्वावलंबी बनाने एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन की पहल पर ऑटो ऋण स्वीकृत कराकर क्रय किये गये ऑटो की चाबी जिला कलक्टर लोकबंधु द्वारा मंगलवार को कलैक्ट्रेट परिसर में दिव्यांग दुरब सिंह को सौंपी।

ज्ञातव्य है कि दिव्यांग दुरब सिंह ने अपनी पीड़ा तत्कालीन जिला कलक्टर आलोक रंजन को बताते हुए कहा कि वह 80 प्रतिशत दिव्यांग है और किराए पर ऑटो लेकर चलाता है उसकी इच्छा है कि वह अपना खुद का ऑटो खरीदें, जिससे किराए पर लिये गये ऑटो के पैसों की बचत से वह अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण के साथ ही अपने बच्चों को अच्छी दिला सके। उसकी बात को तत्कालीन जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए एलडीएम भूपेन्द्र जैन को दुरब सिंह की हरसंभव मदद करने के लिए निर्देश दिये जिस पर एलडीएम जैन ने दुरब सिंह की ऋण पत्रावली तैयार कराकर एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में पहुंचाई और लगातार मॉनिटरिंग के पश्चात एसबीआई शाखा रूपवास द्वारा नया ऑटो खरीदने के लिए लोन स्वीकृत किया गया। दिव्यांग दुरब सिंह को ऋण स्वीकृत होने के पश्चात उसके सामने समस्या आने पर वह वर्तमान जिला कलेक्टर लोकबंधु को अपनी पीड़ा बताने के लिए कार्यालय पहुंचा और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिला कलक्टर ने उसकी समस्या का समाधान कर ऑटो दिलवाया और मंगलवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने दुरब सिंह को बधाई दी व ऑटो की चाबी प्रदान करते हुए यातायात नियमों का पालन करने को कहा।

इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि 80 प्रतिशत दिव्यांग दुरब सिंह ने अपने बुलंद हौसलों से समाज के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत के रूप में है कि उसने अपनी लगन एवं मेहनत से परिवार के स्वावलंबन एवं स्वरोजगार अपनाकर बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि समाज के पीड़ित एवं शोषित वर्ग के लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन सदैव तत्पर है। दिव्यांग ऑटो चालक दुरब सिंह ने जिला कलेक्टर लोकबंधु का आभार व्यक्त किया और लोगों से आह्वान किया कि कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए कठिनाइयां इंसान को सही मायने में जीवन जीने का अनुभव प्रदान करती हैं।